माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2021–22 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस माननीय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2018–19 के पहले बजट से ही हमने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा के साथ गति प्रदान की। हमने जन आकाँक्षाओं को समझते हुए सरकार के सभी विभागों में नई तथा सार्थक योजनाओं के माध्यम से जो पहल की उसके सकारात्मक परिणाम आज हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। सरकार ने तीन वर्ष के कार्यकाल में अपनी नीति और नीयत के केन्द्र में केवल जनहित को रखा है।

हार हो जाती है जब मान लिया जाता है।
जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।।

3. प्रदेश हित के स्वप्न को साकार करने की कार्य योजना को जब हमने वर्ष 2020–21 का बजट प्रस्तुत करते हुए इस माननीय सदन के समक्ष रखा था तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि पूरी दुनिया एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करने जा रही है। नोवल कोरोना वायरस ने सारे विश्व को जिस तेज़ी से अपनी चपेट में लिया उसका कोई दूसरा उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलता। इस महामारी ने दुनिया भर में जिस तरह से भय, चिंता, अनिश्चितता और आर्थिक आपदा का माहौल पैदा किया, उसने कुछ ही सप्ताह में एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट खड़ा कर दिया। दुनिया के सम्पन्न से सम्पन्न राष्ट्र भी इस आपदा के आगे पंगु दिखाई दिए। विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद इस बीमारी के संक्रमण को रोकना असम्भव होता गया। चौबीस घंटे व्यस्त रहने वाले बाज़ार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सुनसान हो गए। एक के बाद एक दुनिया भर के देश लॉकडाऊन करने के लिए विवश हो गए। इलाज़ के लिए न तो दवा थी न ही रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन। दुनिया में हर क्षण बढ़ते मामलों, दुःखदायी मौतों और आर्थिक तबाही के साथ–साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों ने सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी जिसके दुष्प्रभावों से कोई

भी अछूता नहीं रहा। अजीब द्वंद था। अगर एक तरफ इस महामारी से बचने के लिए सब कुछ बन्द कर देने, सारे काम धन्धे रोक देने का विकल्प था तो इससे उत्पन्न स्थिति भी जीवन को संकट में डालने वाली थी। हमें ज्ञात था कि महामारी को फैलने से न रोका गया तो जीवन नहीं बचेगा परन्तु यह भी सत्य था कि आजीविका के बन्द होने पर भी जीवन नहीं बचेगा। हमें आजीविका को भी बचाना था और जीवन को भी। यह असामान्य परिस्थिति थी।

भूख से या वबा (बीमारी) से मरना है।
यह फैसला आदमी को करना है।।

4. चुनौती अभूतपूर्व थी परन्तु चुनौती का सामना करने का जज़्बा भी अभूतपूर्व था। हम कोरोना का न केवल साहस और सफलता से सामना कर रहे हैं अपितु इस वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों को भी कम कर पाये हैं।

5. अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना महामारी के समय Health Care Workers और Front Line Workers, जिन्होंने इस महामारी के समय अपनी जान की परवाह किये बगैर प्रदेश की जनता की तत्परता से सेवा की, को नमन् करते हुये उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

6. महामारी के दौरान दुनिया में लाखों जीवन कोरोना की आहुति चढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कई परिवारों के चिराग इस महामारी के कारण बुझ गए। मैं उन सभी को अपनी और इस माननीय सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवम् परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके परिवारजनों को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करे।

7. यह हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है कि इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भारत का नेतृत्व यशस्वी और दृढ़ इच्छाशक्ति के स्वामी हमारे श्रद्धेय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के हाथ में है। कोरोना काल में उनके सशक्त और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि भारत न केवल इस महामारी से तमाम बाधाओं के बावजूद सफलतापूर्वक लड़ रहा है बल्कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। हम भारतवासियों के साथ–साथ दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। हमारी यह उपलब्धि 'वसुदैव कुटुम्बकम' की समृद्ध सांस्कृतिक

विरासत एवम् वैज्ञानिकों की दक्षता का प्रतीक है। निराशा के लम्बे समय के बाद उम्मीद के सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। हमने यह साबित किया है कि कोई भी संकट मानवता की सामूहिक शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता।

रोक सकता है तू लहरों को,
कोशिश करके तो देख,
लौटा सकता है तू तूफ़ां को,
कोशिश करके तो देख।
मुसीबतें खड़ी हैं जो सीना ताने तेरे सामने,
सर झुकाएंगी एक दिन, कोशिश करके तो देख।।

8. प्रदेश वासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि 25 जनवरी, 2021 को हमने अपने पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम पचास वर्ष पूरे करके 51वें (इक्यावनवें) वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि 2020 को स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश भर में भव्य आयोजन किये जाएंगे, जिससे कि नई पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास को जानने और हमारी देव भूमि और वीर भूमि की समृद्ध परम्पराओं से अवगत होने का अवसर मिले। नोवल कोरोना वायरस ने इन आयोजनों पर तो रोक लगा दी परन्तु हमें बहुत कुछ नया सीखने और नया करने के अवसर प्रदान किये। हमने निर्णय लिया है कि अब ये आयोजन 2021–22 में किये जाएंगे। प्रदेश सरकार पाँच दशक की विकास गाथा को 'स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा' के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश वासी तक पहुँचाएगी। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए 'भविष्य का दृष्टिपत्र' भी तैयार करेगी।

हर बाधा से जीत रहे हम,
मिल कर सपने सींच रहे हम।
पीढ़ी दर पीढ़ी जन मन के तप का हासिल है,
ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है।।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

9. पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का प्रतिकूल प्रभाव रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण भारी संकुचन देखा गया और पहली तिमाही में माईनस 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई परन्तु

सरकार के निरन्तर प्रयासों से वर्ष के अन्त तक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तथा यह गिरावट कम होकर केवल माईनस 7.7 प्रतिशत रह गई। इतना ही नहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में आगामी वर्ष में 11 (ग्यारह) प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। लॉक डाऊन और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की सुनियोजित रणनीति के चलते हम आज आर्थिक रिकवरी के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। यह अत्यन्त आशाजनक एवं उत्साहवर्धक स्थिति है। इस वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर Negative से उभरकर Positive पर आ गई है। V-Shaped (V-आकार) की इस recovery के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना' और 27 (सत्ताईस) लाख करोड़ रुपये की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'जरूरतमंद लोगों के खातों में पैसे का सीधा हस्तांतरण' जैसी कल्पनाशील, नवाचारी और दूरंदेशी योजनाओं का योगदान है।

हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को,
सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

10. हमारी सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 2020–21 के दौरान केवल माईनस 6.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ होने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित गिरावट से 1.5 प्रतिशत अंक कम है। 2020–21 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,56,522 (एक लाख छप्पन हज़ार पाँच सौ बाईस) करोड़ रुपये रहेगा। 2020–21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 (एक लाख तिरासी हज़ार दो सौ छियासी) रुपये रहने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 (छप्पन हज़ार तीन सौ अट्ठारह) रुपये अधिक है।

विकास बजट

11. अध्यक्ष महोदय, 2021–22 से बजट का स्वरूप बदल रहा है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश बजट में भी योजना एवम् गैर–योजना मदों का भेद समाप्त कर दिया गया है। बजट दस्तावेज़ों में बजटीय प्रावधान केवल राजस्व परिव्ययों एवम् पूंजीगत परिव्ययों के आधार पर ही किये जाएंगे। अनुसूचित जाति उप–योजना का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम' तथा जनजातीय उप–योजना का नाम बदलकर 'जन–जातीय क्षेत्र विकास

कार्यक्रम' रखा गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल विकासात्मक परिव्ययों की क्रमशः 25.19 प्रतिशत एवम् 9 प्रतिशत परिव्यय रखने की व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।

12. 2021–22 के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए 9,405 (नौ हज़ार चार सौ पाँच) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,369 (दो हज़ार तीन सौ उनहत्तर) करोड़ रुपये तथा जन–जातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 846 (आठ सौ छयालीस) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 93 (तिरानबे) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। बजट के बदले प्रारूप के दृष्टिगत् मैं **'योजना विभाग'** का नाम बदलकर **"नीति विभाग"** रखना प्रस्तावित करता हूँ।

13. संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत समय से चली आ रही कुछ योजनाओं का युक्तिकरण किया है। 2021–22 में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

14. सदी के सबसे गम्भीर संकट के बावजूद 15वें वित्तायोग की 2020–21 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए समुचित अनुदान की व्यवस्था की गई है। मैं भारत सरकार तथा 15वें वित्तायोग का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

15. केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दो किश्तों में 450 (चार सौ पचास) करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया है। इस ऋण का भुगतान 50 (पचास) वर्ष के बाद किया जाएगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है जिसके लिए हम केन्द्र सरकार का धन्यवाद करते हैं।

16. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्षों में 2,382 (दो हज़ार तीन सौ बयासी) करोड़ रुपये की लागत से 639 (छः सौ उनतालीस) विधायक प्राथमिकता योजनायें नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई हैं। हमारी सरकार ने न

केवल DPRs बनाने की प्रक्रिया तेज़ की है बल्कि उन्हें नाबार्ड से स्वीकृत करवाकर उनके कार्यान्वयन को भी गति दी है। मैं माननीय सदस्यों से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार निजी भूमि उपलब्ध करवाने में सहयोग करने की अपील करता हूँ।

17. माननीय विधायकों के साथ 8 और 9 फरवरी, 2021 को हुई बैठकों के दौरान उनसे प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत् मैं 2021–22 के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- 'विकास में जन सहयोग' कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाकर दोगुना किये जाएंगे।
- नाबार्ड को RIDF के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 (एक सौ बीस) करोड़ रुपये से बढ़ाकर 135 (एक सौ पैंतीस) करोड़ रुपये किया जाएगा।
- 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत विकट वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत् जारी की जाने वाली राशि को अप्रैल, 2020 में suspend किया गया था। तदोपरान्त जनहित को देखते हुए इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया था तथा 50 (पचास) लाख रुपये की निधि जारी की गई थी। 2021–22 में इस निधि को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा तथा मैं इसे वर्तमान में 1.75 करोड़ (एक करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये से बढ़ाकर 1.80 करोड़ (एक करोड़ अस्सी लाख) रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही माननीय विधायक महिला मण्डलों तथा युवक मण्डलों के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों के लिए भी इस निधि में से अधिकतम 50,000 (पचास हजार) रुपये तक की अनुशंसा कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

18. अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत् माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में मन्त्रियों एवम् सांसदों द्वारा पहल करते हुए एक साल के लिए वेतन में 30

प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्णय लिया। मैं प्रदेश के सभी माननीय मन्त्रियों, माननीय विधायकों तथा विभिन्न बोर्डों एवम् निगमों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी इस आपदा से निपटने के लिए अपने वेतन तथा मानदेय में से एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत अँशदान प्रदान करने का निर्णय लिया। मैं यह घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2021 से ये वेतन तथा मानदेय बहाल कर दिये जाएंगे।

डिजिटाईजेशन

19. अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाईन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने में सफल रहे हैं। इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगामी वर्षों में सरकारी सेवा निष्पादन की अधिकाँश प्रक्रियाओं को Digitize करके और प्रभावी बनाया जाएगा। आगामी वर्ष में इस दिशा में निम्न कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैंः–

- शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में Integrated Command and Control Centre की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न शहरी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित एवं प्रबन्धित करेगा।

- 'स्वर्ण जयन्ती सम्पर्क संकल्प' के अन्तर्गत प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों में चरणबद्ध ढंग से Video Conferencing की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लगभग 60 (साठ) करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

- ITI संस्थानों में भी वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा शुरु की जाएगी।

- हिमाचल ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध 65 (पैंसठ) सेवाओं को बढ़ाकर 80 (अस्सी) किया जाएगा तथा इन्हें लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।

- 'निजी शैक्षणिक संस्थायें नियामन आयोग' निजी शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित सूचना, प्रबन्धन एवम् निगरानी के उद्देश्य से Management Information System स्थापित करेगा।

- केन्द्र सरकार की तर्ज़ पर राज्य योजनाओं को भी Public Finance Management System प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए एक 'Beneficiary Data Base Management System' स्थापित किया जाएगा जिससे लाभार्थियों के चयन में सुविधा होगी।

सुशासन

20. अध्यक्ष महोदय, हम पारदर्शी, उत्तरदायी तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हैं। हमने सत्ता में आने के बाद से बदले की भावना की दलगत राजनीति का चलन समाप्त कर दिया है।

21. शासन में पारदर्शिता तथा सरकारी सेवाओं की तत्काल उपलब्धता के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। आगामी वर्ष में शासन को सुदृढ़ करने के लिए निम्न कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैंः–

- प्रदेश में ज़िला स्तर पर सुशासन हेतु उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा तथा Innovation को प्रोत्साहित करने के लिए "Swaran Jayanti District Innovation Fund" स्थापित किया जाएगा।

- सरकारी अधिकारियों की सम्पत्ति से जुड़ी सूचना में पारदर्शिता लाने के लिए 2021–22 से सभी Class-I एवं Class-II अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा, वार्षिक आधार पर, अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरना होगा।

- 'Ease of Doing Business' एवम् 'Ease of Living' को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने नियमों, अधिनियमों, प्रक्रियाओं आदि में आवश्यक संशोधन करेगा।

- सभी विभागों के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा।

गृहिणी सुविधा योजना

22. हमारी सरकार नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनायें लागू कर रही है। गृहिणी सुविधा योजना इसी कड़ी में हमारी महत्वपूर्ण पहल है जिसने पूरे

प्रदेश की गृहिणियों को बीमारियों, प्रदूषण और रोज़मर्रा के अनावश्यक कठिन श्रम से मुक्ति दिलाई है।

23. 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' के अन्तर्गत अब तक लगभग 2,92,000 (दो लाख बानवे हज़ार) गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आगामी वर्ष में नये पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे तथा मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत् रखा जाएगा। 2021–22 में इस योजना में 20 (बीस) करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

स्वामी विवेकानन्द ने कहा हैः–

स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं, किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितान्त असम्भव है।

24. सामाजिक दूरी के महत्व को समझते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग, राशन की दुकानों पर IRIS स्कैनिंग से बॉयोमिट्रिक ट्रांजेक्शन की संभावना पर कार्य करेगा। इससे राशन उपलब्ध कराने में अधिक सुविधा होगी।

कृषि एवं सिंचाई

25. कोरोना के बावजूद प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने अर्थव्यवस्था को बल दिया। कृषि मनुष्य को सम्पत्ति और प्रतिभा प्रदान करती है। कृषि प्राणियों के जीवन का आधार है। हमारी सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनायें राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति हमारे सम्मान का परिचायक हैं।

26. प्रदेश के पाँच जिलों में जापान की सहायता से चलाई जा रही JICA परियोजना के पहले चरण की सफलता को देखते हुए इसके दूसरे चरण को सभी बारह जिलों में चलाया जाएगा। 1,055 (एक हज़ार पचपन) करोड़ रुपये की इस परियोजना को 2021–22 से शुरु किया जाएगा जिसके लिए सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। विविधिकरण एवम् value addition के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 2021–22 के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियां की जाएंगी जिनमें मुख्यतः लगभग 60 (साठ) DPRs बनाना,

कृषक विकास संघों से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण, प्रदेश की मंडियों का आधुनिकीकरण इत्यादि सम्मिलित हैं।

27. प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही 'प्राकृतिक खेती–खुशहाल किसान' योजना के अन्तर्गत 'सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि' के सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए हैं। अभी तक इस पद्धति को 1,05,218 (एक लाख पाँच हज़ार दो सौ अठारह) किसानों ने अपनाया है। आगामी वर्ष में 50 (पचास) हज़ार नये किसान परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त एक लाख किसान परिवारों को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्राकृतिक उत्पादों को बाजार में अलग पहचान मिले, इसके लिए इस पद्धति से जुड़े किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण किया जाएगा और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। मैं इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 2021–22 में 20 (बीस) करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

28. हमारी सरकार 2021–22 में परम्परागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु नई "स्वर्ण जयन्ती परम्परागत बीज संरक्षण एवम् संवर्धन योजना" (SJBSY) आरम्भ करेगी। इसके तहत पहाड़ी दालों, परम्परागत अनाजों और बेमौसमी फसलों के लिए बीज से बाजार तक की एक समग्र कार्य योजना बनाई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों एवं किसान उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

29. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बजट भाषण में वर्णित 6 स्तम्भों में से एक स्तम्भ नवाचार, अनुसन्धान एवं विकास है। इसके अनुरूप प्रदेश के कृषि तथा बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 (पाँच) करोड़ रुपये का अनुसन्धान कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जाएंगे।

30. प्रदेश के किसानों अथवा उत्पादकों को उनकी उपज के विपणन हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 63 (तिरेसठ) मंडियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में 3 (तीन) नई मंडियों – मेंहदली और शिलारु, ज़िला शिमला; तथा बन्दरोल, ज़िला कुल्लू के निर्माण तथा 20

(बीस) वर्तमान मंडियों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण कार्य को 2021–22 में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 200 (दो सौ) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। प्रदेश की 19 (उन्नीस) वर्तमान मंडियों के अतिरिक्त 10 (दस) मंडियों को ई–नाम व्यवस्था से जोड़ने की चल रही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश की कृषि मंडियों में फूलों का व्यापार करने में किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सम्बन्धित एक्ट में इसके लिए अभी उचित प्रावधान नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि फूलों के व्यापार को HP Agricultural, Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 के schedule में शामिल किया जाएगा।

31. अध्यक्ष महोदय, सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'हिमकैड' योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में 15,242 (पन्द्रह हज़ार दो सौ बयालीस) हैक्टेयर क्षेत्र को Command Area Development के अन्तर्गत लाया जा चुका है। 2021–22 में इस योजना पर 83 (तिरासी) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है। इन परिव्ययों की सहायता से 4,000 (चार हज़ार) हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

किसान का बेटा हूँ खेती करना मेरा कर्म है,
अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है।

बागवानी

32. हमारी सरकार के लिए बागवानी विकास सदैव से प्राथमिकता रही है। किसानों व बागवानों के अथक् प्रयासों से राज्य ने गत् 50 (पचास) वर्षों में बागवानी में कई नए आयाम स्थापित किये हैं।

33. लगभग 1,000 (एक हज़ार) करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत 2021–22 में प्रदेश में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाएंगीः–

- पाँच लाख पौधों का आयात।
- दो सौ जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से 8 (आठ) हज़ार हैक्टेयर पर Command Area Development के लिए सिंचाई सम्बन्धित कार्य।

- Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni में Gene Repository की स्थापना।
- जरोल–टिक्कर, रोहड़ू, ओडी, पतली कूहल तथा टुटूपानी में CA Stores तथा Pack Houses का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
- पराला, शिमला स्थित संयन्त्र में Apple Juice Concentrate Plant की स्थापना।

34. सब–ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ADB की सहायता से लगभग 10 (दस) मिलियन अमेरिकी डॉलर की पायलट योजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी।

35. मैं प्रदेश के बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के High Density पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए नई "स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान" योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

36. 'कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना' (KUSHY) के अन्तर्गत 2021–22 में भी किसानों और बागवानों को हेलनेट के लिए उपदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना अत्यन्त लोकप्रिय है। उल्लेखनीय है कि 2017–18 में Anti Hailnet पर उपदान के लिए मात्र 2.27 करोड़ (दो करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये का प्रावधान था। पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकार द्वारा इस योजना के दायरे को बढ़ाया गया। आगामी वर्ष के दौरान इसके लिए 60 (साठ) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे जो कि 2020–21 से 10 करोड़ रुपये अधिक हैं।

37. प्रदेश में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवम् मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से मैं "राज्य मधुमक्खी बोर्ड" (State Bee Board) के गठन की घोषणा करता हूँ।

38. 2021–22 के दौरान 'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना' के तहत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 (ग्यारह) करोड़ रुपये के प्रावधान से लगभग एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र में हरित गृहों की स्थापना की जाएगी।

बागवानी क्षेत्र के लिए 2021–22 में 543 (पाँच सौ तैंतालीस) करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन विभाग/ गौ–संरक्षण

39. अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को उच्च श्रेणी की विशेषज्ञ सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 (तीन) जोनल अस्पतालों, 10 (दस) वैटरीनरी पॉली क्लिनिक को आधुनिक उपकरण उपलबध करवाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त उप–मण्डलीय स्तर के वैटरीनरी संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए 2021–22 में 5 (पाँच) करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जाएंगे।

40. गौ सेवा के प्रति मेरी सरकार समर्पित है। प्रदेश में स्थित गौ अभ्यारण्य और गौ सदनों के माध्यम से प्रति गौवंश एक निश्चित अनुदान दिया जा रहा है। इस सेवा के लिये यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो। ताल एवम् ज्योरी स्थित भेड़ प्रजनन फॉर्म एवम् पालमपुर तथा बागथन स्थित गाय प्रजनन फॉर्मों को चारा उत्पादन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

41. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध खरीद मूल्य 2 (दो) रुपये बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। 2021–22 में मिल्कफैड को 28 (अट्ठाईस) करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

42. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मछली उत्पादकों को उचित मार्किटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि मंडियों की तर्ज़ पर गोबिंदसागर तथा पौंग डैम जलाशयों के उत्पाद हेतु अत्याधुनिक मछली क्रय–विक्रय केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। इससे क्षेत्र के मछली उत्पादकों को अपना उत्पाद उचित मूल्य पर बेचने में सुविधा होगी।

43. सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए शिमला व काँगड़ा में निजी क्षेत्र में एक–एक इकाई स्थापित की जाएगी। ज़िला काँगड़ा में एक Bioflock इकाई स्थापित की जाएगी। आगामी वर्ष में 100 (सौ) नई ट्राऊट इकाईयों का निर्माण भी किया जाएगा।

कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए समग्र योजना

44. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमन्त्री जी ने Climate Change Resilient Agriculture का आह्वान किया है। आज भी प्रदेश के लगभग 90 (नब्बे) प्रतिशत परिवार कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ग्राम स्तर पर किसान परिवार एक समग्र इकाई है जो एक साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन, मधुमक्खी

पालन, मत्स्य पालन एवं अन्य सम्बन्धित व्यवसायों एवम् कार्यकलापों से जुड़ा रहता है। अलग–अलग विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से उसी किसान परिवार तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

45. ऐसा देखा गया है कि कई बार इन योजनाओं में दोहराव होता है और समय, धन और प्रयास का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। मैं किसान परिवार को केन्द्र में रख कर सम्बन्धित विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को पुनर्परिभाषित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस महत्वकाँक्षी कार्ययोजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक Expert Group गठित करना प्रस्तावित करता हूँ। यह Expert Group किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी संस्तुति भी देगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ। किसान की पीड़ा समझता हूँ।

चीर के ज़मीन को उम्मीद के बीज बोता हूँ,
किसान हूँ, सींचता हूँ लहू से तब फसल देता हूँ।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

46. अध्यक्ष महोदय, हाल ही में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिप्रिय और सफलतापूर्वक ढंग से पूर्ण हुए हैं। इन चुनावों में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और मुझे प्रसन्नता है कि इन चुनावों में प्रदेश सरकार की नीतियों को भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। नये चुने गए पंचायती और शहरी निकायों के सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इन चुनावों में 102 (एक सौ दो) ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने अपने सभी प्रतिनिधि निर्विरोध चुने हैं। ऐसी पंचायतें 10 (दस) लाख रुपये प्रति पंचायत की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र हैं।

47. 2005 के बाद प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया था जबकि भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत् नई पंचायतों के गठन की लगातार माँग की जा रही रही थी। हमारी सरकार ने 412 (चार सौ बारह) नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। अब प्रदेश में

ग्राम पंचायतों की संख्या 3,615 (तीन हज़ार छः सौ पन्द्रह) हो गई है।

48. मैं घोषणा करता हूँ कि सभी नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

49. पांचवें राज्य वित्तायोग की सिफ़ारिशों के तहत 2021–22 में 248 (दो सौ अड़तालीस) करोड़ रुपये की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्राप्त 409 (चार सौ नौ) करोड़ रुपये इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास पर खर्च किये जाएंगे।

50. प्रदेश के पाँच जिलों – काँगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मण्डी और बिलासपुर में पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय संसाधन केन्द्र का निर्माण किया जा चुका है। किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2021–22 में कुल्लू तथा ऊना ज़िलों में ज़िला संसाधन केन्द्रों के निर्माण को प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

51. पंचायतों में एक छत के नीचे सभी IT Related Services प्रदान करने के लिए 'कॉमन सर्विस सेंटर' स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 598 (पाँच सौ अठानवे) सेंटर निर्माणाधीन हैं। 2021–22 में 2,982 (दो हज़ार नौ सौ बयासी) सेंटर बनाये जाएंगे जिनके निर्माण पर 149 (एक सौ उनचास) करोड़ रुपये की लागत आएगी।

52. 'पंचवटी' योजना के अन्तर्गत 2020–21 में 364 (तीन सौ चौंसठ) स्थानों पर भूमि का चयन किया जा चुका है तथा 180 (एक सौ अस्सी) स्थानों पर कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। 2021–22 में 100 (सौ) और स्थानों पर इस योजना के अन्तर्गत पार्क बनाये जाएंगे।

53. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक उपयोगी माध्यम है। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

54. 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अन्तर्गत 5,500 (पाँच हज़ार पाँच सौ) स्वयं सहायता समूहों को 8.25 करोड़ (आठ करोड़ पच्चीस लाख) रुपये का revolving fund तथा 1,500 (एक हज़ार पाँच सौ) स्वयं सहायता समूहों को 7.50 करोड़ (सात करोड़ पचास लाख) रुपये सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूँ।

55. स्वयं सहायता समूह में अधिक उद्यमिता को लाने के लिए एक सुविचारित एवं सुनियोजित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 3 (तीन) लाख रुपये तक की राशि के ऋण पर एक निश्चित ब्याज उपदान दिया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे स्वयं सहायता समूह, जो अपनी गतिविधियों तथा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 5 (पाँच) लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 (दो) लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण पर इसी दर पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान पर 10 (दस) करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान है।

56. स्वयं सहायता समूहों को अपने काम को बेहतर करने के लिए तथा अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए कई प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ 100 (सौ) स्वयं सहायता समूहों को इस उद्देश्य के लिए, कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र जारी किये जाएंगे। हमारी सरकार की इन दोनों पहलों को मैं एक नई "स्वर्ण जयन्ती SHG सहयोग" (SJSS) योजना के अन्तर्गत लाने की घोषणा करता हूँ।

57. स्वयं सहायता समूहों के आजीविका अवसरों में वृद्धि के लिये, पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एक नई योजना **"हिम–ईरा रसोई" Canteen** आरम्भ की जाएगी। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये, उनकी भागीदारी से सिरमौर जिला में 'She Haat' की प्रारम्भिक सफलता के दृष्टिगत् इस मॉडल को अन्य जिलों में भी स्थापित किया जाएगा।

58. धातु, पत्थर व लकड़ी की नक्काशी का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना' के अन्तर्गत 2021–22 में एक हज़ार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवम् 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' के अन्तर्गत 1,000 (एक हज़ार) लाभार्थियों को जॉब प्लेसमैंट देने की मैं घोषणा करता हूँ।

59. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत 100 (सौ) सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 16 (सोलह) Plastic Waste Management Plants एवम् 12 (बारह) गोवर्धन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2,400 (दो हज़ार चार सौ) गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की गतिविधियां शुरु की जाएंगी।

60. दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से 250 (दो सौ पचास) महिलाओं को "Bank Correspondent Sakhi" सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

61. मैं पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 300 (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

वन संरक्षण एवं वनों से रोज़गार

62. पिछले बजट में मैंने 2030 तक प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मौजूदा वृक्ष आवरण को 27.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का संकल्प प्रस्तुत किया था। प्रोत्साहन एवं Disincentive को आधार बनाकर पौधरोपण की नीति में सुधार किया जाएगा जिससे बेहतर survival rate तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। 2020–21 में 12 (बारह) हज़ार हैक्टेयर भूमि में पौधे लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 2021–22 में 14 (चौदह) हज़ार हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगाये जाएंगे।

तमाम दिन जो कड़ी धूप में झुलसते हैं,
वही दरख्त मुसाफ़िर को छाँव करते हैं।

63. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 (पचास) साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार लोगों में स्वस्थ जीवनशैली प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 68 (अड़सठ) स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित करेगी।

64. प्रदेश में 3 (तीन) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रमशः KfW की Forest Ecosystem Climate Proofing Project; JICA की Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystem and Livelihood; तथा, विश्व बैंक पोषित IDP for Source Sustainability and Climate Resilient Rain-Fed Agriculture कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजना के अन्तर्गत 2021–22 में 2 (दो) हज़ार हैक्टेयर भूमि से लैंटाना निवारण, 3 (तीन) हज़ार हैक्टेयर में पौधों का रोपण तथा 7 (सात) हज़ार हैक्टेयर में मृदा, संरक्षण और प्रबन्धन कार्य किये जाएंगे।

65. जंगलों में मिट्टी की नमीं बढ़ाने हेतु वन क्षेत्रों में बहने वाली बारहमासी जल धाराओं में जल भण्डारण बाँधों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक बाँध में लगभग 8 से 10 (दस) लाख लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता होगी। इस योजना पर आगामी 2 वर्षों में 300 (तीन सौ) जल भण्डारण बाँध बनाए जाएंगे जिन पर लगभग 100 (सौ) करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

66. प्रदेश के ऊँचे शुष्क क्षेत्रों लाहौल–स्पिति व किन्नौर में 5 वर्षों के दौरान 250 (दो सौ पचास) हैक्टेयर भूमि पर छरमा के पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। 2021–22 में 50 (पचास) हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा।

67. अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर वृक्ष कटान की अनुमति लेने को हाल ही में सुविधाजनक बनाया गया है। वन मण्डल अधिकारियों/अरण्यपालों की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं ताकि आम जनता को आसानी से अनुमति मिल सके।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

68. इसी वर्ष शोघी (शिमला) में 10 (दस) करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन Science Learning and Creativity Centre जनता को समर्पित किया जाएगा। इसी स्थान पर प्रदेश के पहले बहुप्रतीक्षित Planetarium का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा जिसके निर्माण पर लगभग सात करोड़ रुपये व्यय होंगे।

69. भारत सरकार एवम् जर्मन एजैंसी GIZ के सहयोग से जलवायु परिवर्तन Adaption and Mitigation Knowledge के लिए प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।

70. हमारी सरकार ने कचरे के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए शहरी निकायों को एकत्रित प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से संशोधित और निष्पादन करने के लिए 70 (सत्तर) वेस्ट शरैडर, 70 (सत्तर) प्लास्टिक वेस्ट बेलिंग मशीनें और 70 (सत्तर) प्लास्टिक वेस्ट कम्पेक्टर प्रदान किये जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट के स्थाई प्रबन्धन हेतु शहरी निकायों को प्लास्टिक की ईंटें तथा टाईल्स बनाने में तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। अथर्ववेद में कहा गया हैः–

"माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्याः"

अर्थात् यह धरती माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।

71. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' का स्वागत करता है। इस नीति से प्रारम्भिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्चतम स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का श्रेय हमारे प्रधानमन्त्री जी को जाता है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस भविष्योन्मुखी नीति को राष्ट्र को समर्पित किया है। **गुणात्मक शिक्षा**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का आधार सिद्धांत है किः

"शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिन्तन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और धार हो।"

72. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का मूल्याँकन करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 में विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी।

73. पिछले बजट में मैंने व्यवसायिक संस्थानों में मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु प्रशिक्षण के लिए 'स्वर्ण जयन्ती सुपर–100' योजना आरम्भ की थी। इस योजना का विस्तार करते हुए

मैं नई योजना **"टॉप 100 छात्रवृति योजना"** शुरु करने की घोषणा करता हूँ जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरान्त 100 (सौ) प्रतिभाशाली छात्रों का चयन SCERT द्वारा किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्याँकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

74. युवा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु मैं प्रस्तावित करता हूँ कि शिक्षा विभाग पायलट आधार पर विज्ञान, गणित तथा spoken English में विशेष कोर्स आरम्भ करेगा। आगामी वर्ष में विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में भी 100 (सौ) Maths Labs स्थापित की जाएंगी तथा बच्चों की बौद्धिक क्षमता विकास हेतु शतरंज के खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कर्तव्यों का बोध कराती
अधिकारों का ज्ञान,
शिक्षा से ही मिल सकता है
सर्वोपरि सम्मान।

75. प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्यों के दृष्टिगत् 'हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल' स्थापित किया जाएगा। मोबाईल ऐप की सहायता से भी इस पोर्टल पर अध्यापन एवं कार्मिक मामलों से सम्बन्धित सूचना अपलोड की जा सकेगी।

76. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में ब्लॉक, ज़िला और राज्य स्तर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मैं विभिन्न टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों के लिए डाइट मनी की दर को दोगुना करने की घोषणा करता हूँ। यह डाईट मनी ब्लॉक स्तर पर 50 (पचास) रुपये से बढ़ाकर 100 (सौ) रुपये, ज़ोनल और ज़िला स्तर पर 60 (साठ) रुपये से बढ़ाकर 120 (एक सौ बीस) रुपये और राज्य स्तर पर 75 (पचहत्तर) रुपये से बढ़ाकर 150 (एक सौ पचास) रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र की जाएगी।

77. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा 2018–19 में 'मेधा प्रोत्साहन योजना' आरम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे मेधावी बच्चों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश से बाहर कोचिंग लेना चाहें, के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना

के अन्तर्गत 838 (आठ सौ अड़तीस) लाभार्थियों को लगभग 2.19 करोड़ (दो करोड़ उन्नीस लाख) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हमारी सरकार प्रदेश में मेधा को प्रोत्साहित करने के लिए यथासम्भव प्रयास करती रहेगी।

78. हमारे मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। कोरोना के समय में शिक्षा विभाग ने अपनी विभागीय क्षमता का निर्माण करके डिजिटल माध्यम से 'हर घर पाठशाला' कार्यक्रम से प्रदेश के दूर–दराज़ क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बनाई और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिससे कि तकनीक और उपलब्ध मानव संसाधनों के परस्पर सहयोग से सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके और उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं कैरियर काऊंसलिंग की उचित व्यवस्था हो सके। इस पहल के अन्तर्गत ऑनलाईन तथा ऑफलाईन modes में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैं बजट में 5 (पाँच) करोड़ रुपये का प्रावधान रखता हूँ।

79. राज्य सरकार 'श्रीनिवास रामानुजम योजना' के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध करा रही है। प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव के फलस्वरूप अब लैपटॉप के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस सन्दर्भ में वर्तमान में चल रही व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

80. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया तथा गुणवत्ता को केन्द्र बिन्दु बनाया। इस सन्दर्भ में तीन योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा– 'स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना', 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना' तथा महाविद्यालयों के लिए 'उत्कृष्ट योजना'। आगामी वर्ष में इन तीनों योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 100 (सौ) क्लस्टर स्कूल, 68 (अड़सठ) वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 9 (नौ) महाविद्यालय शामिल किये जाएंगे। इन स्कूलों में आवश्यक, आधुनिक सुविधाओं तथा अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मैं 2021–22 में इन तीनों योजनाओं

के लिए 63 (तरेसठ) करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

81. Convergence के सिद्धांत पर हमारी सरकार ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 100 (सौ) अन्य स्कूलों में भी सुविधाओं का उन्नयन करेगी।

82. मैं स्कूल प्रबन्धन कमेटी (SMC) द्वारा रखे गये सभी वर्ग के अध्यापकों के मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों में आऊटसोर्स आधार पर सेवायें दे रहे IT शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। मैं विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की माँगों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा करता हूँ।

83. हमारी सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021–22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड–डे–मील वर्कर के लिए हाईजीन किट उपलब्ध करवाएगी। मैं मिड–डे–मील वर्करज़ तथा वॉटर कैरियरज़ के मासिक मानदेय को 300 (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021–22 में 8,024 (आठ हज़ार चौबीस) करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

84. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं को टूल किट के लिए उपदान दिया जा रहा है। अन्य वर्गों को भी टूलकिट की खरीद में अनुदान देने के लिए दिशा–निर्देश बनाये जाएंगे।

85. 2021–22 में तकनीकी संस्थानों क्रमशः सिविल ब्लॉक Mahatma Gandhi Government Engineering College कोटला (ज्योरी); मकैनिकल इंजिनियरिंग ब्लॉक, सुंदरनगर; ITI कुमारसैन का ब्लॉक 'बी'; ITI अर्की में वर्कशॉप ब्लॉक; ITI भवन गंगथ; ITI भवन करसोग; महिला राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, रैहन; तथा बन्दला स्थित हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा करके इन्हें प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इनके निर्माण में

लगभग 400 (चार सौ) करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा शिक्षा

86. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के लोगों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी प्रयास करने के लिए कृतसंकल्प है। हाल ही में हुए National Family Health Survey-5 के आधार पर आई रिपोर्ट पर हमारी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। बच्चों में Stunting, Wasting तथा कुपोषण एवं अनीमिया को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की भागीदारी से एक एकीकृत पहल की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूँ कि 2021–22 में प्रदेश सरकार नीति आयोग की भागीदारी से एक study करवाएगी जिसके आधार पर इस समस्या के निदान के लिए एक Action Plan बनाया जाएगा।

87. वर्तमान में राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में Positron Emission Tomography (PET) स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कैंसर के मरीज़ पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए बाध्य होते हैं फलस्वरूप उन्हें बहुत राशि खर्च करनी पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए PET स्कैन की सुविधा IGMC शिमला में स्थापित की जाएगी। साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज में CT Scan तथा MRI मशीनें; एवम् हमीरपुर तथा नाहन मेडिकल कॉलेज में CT Scan मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए 70 (सत्तर) करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार AIIMS बिलासपुर और PGI Satellite Centre ऊना जैसी शीर्ष स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सरकार का आभार व्यक्त करती है। मैं घोषणा करता हूँ कि शिमला के चमयाना में 278 (दो सौ अठ्हत्तर) करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सुपर स्पैशलिटी अस्पताल को 2021–22 में जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इसी के साथ इन्दिरा गान्धी मैडिकल कॉलेज, शिमला में 103 (एक सौ तीन) करोड़ रुपये की लागत से बन रहे न्यू OPD Block एवम् लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले ट्रॉमा सेंटर को भी इसी वर्ष क्रियाशील कर दिया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज के Super Speciality Ward को भी सुदृढ़

किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम प्रदेश के लिए अधिक से अधिक Super Specialists को आकर्षित कर सकें।

89. गत तीन वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के Tertiary Sector में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज शिमला, टाण्डा, नाहन, हमीरपुर, चम्बा और नेरचौक तथा दन्त चिकित्सा कॉलेज शिमला के आधारभूत ढाँचे और इनमें समुचित सेवाओं पर 2020–21 में 772 (सात सौ बहत्तर) करोड़ रुपये खर्च होंगे। जब हम सरकार में आये थे तो यह परिव्यय 554 (पाँच सौ चौवन) करोड़ रुपये था। पिछले 3 वर्षों में इसमें 28(अट्ठाईस) प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

90. 'हिमकेयर' योजना में लगभग 1,600 (एक हज़ार छः सौ) पैकेज सम्मिलित हैं। आवश्यकता अनुसार इनके दायरे को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि 2021–22 में 70 (सत्तर) वर्ष से अधिक आयु के सभी 'हिमकेयर' के लाभार्थियों तथा सभी अनाथ बच्चों, जो कि बाल आश्रमों में रह रहे हैं, को हिम केयर योजना में, बिना अँशदान दिये, शामिल किये जाएंगे।

91. मैं माननीय सदन को यह भी सहर्ष अवगत करवाना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत, हिम केयर, मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, निःशुल्क दवाईयां, सहारा योजना, सम्मान योजना, निक्षय पोषण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश सरकार 2021–22 में 250 (दो सौ पचास) करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेगी।

92. बच्चों में दृष्टि दोष और अन्धापन स्वास्थ्य सेवा नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है। इन बच्चों को बाल्यवस्था में दृष्टि सुधार की आवश्यकता होती है। मैं कक्षा छः से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आँखों की जाँच एवं निःशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए "मिशन दृष्टि" आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

93. मुझे यह बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज में प्रदेश देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। मातृ एवं बाल देखभाल सुविधाओं को एकीकृत रूप में प्रदान किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य उप–केन्द्रों और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीमों को

डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध करवाए जाएंगे जो एनीमिया का समय पर पता लगाने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

94. पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग में निमोनिया मृत्यु का एक मुख्य कारण है। हमारी सरकार ने निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसी कड़ी में मैं घोषणा करता हूँ कि सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में ऑक्सीमीटर के माध्यम से निमोनिया की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रथम चरण में यह ज़िला चम्बा और मण्डी में शुरु की जाएगी और परिणाम के आधार पर इसका विस्तार किया जाएगा।

95. बचपन में कुपोषण से सम्बन्धित आँकड़े एक चिंता का विषय है। मेरी सरकार इस क्षेत्र में सुधार के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

96. मैं प्रदेश में सेवायें दे रहे PG Students, Junior Residents, Senior Residents, DM/M.ch students के मानदेय को पाँच–पाँच हज़ार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।

97. कोरोना के दौरान आशा वर्कर ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं प्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय में राज्य अँशदान को 750 (सात सौ पचास) रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। गर्भवती महिलाओं को प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिनिकों तक तीसरी निर्धारित प्रसव पूर्व जाँच के लिए ले जाने पर आशा वर्कर को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए 2 (दो) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

98. प्रदेश सरकार 2021–22 में 143 (एक सौ तैंतालीस) 'आयुष वैलनैस सेंटर' स्थापित करेगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग प्रशिक्षित योग मार्गदर्शकों का समूह तैयार करेगा जो निजी क्षेत्र में सेवायें देने के लिए उपलब्ध होंगे।

99. हम सभी जानते हैं कि 'जान है तो जहान है'। यहाँ मैं हमारी सांस्कृतिक परम्परा की उस भावना को दोहराना चाहूँगा जिसे करोड़ों भारतीय प्रतिदिन व्यक्त करते हैं :–

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्।।

अर्थात्

सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुःख का भागी न बने।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2021–22 में 3,016 (तीन हजार सोलह) करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता

100. प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नाबार्ड के सहयोग से 50 (पचास) सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण पायलट आधार पर किया जाएगा। आगामी वर्षों में योजना का विस्तार किया जाएगा जिस पर 10 (दस) करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

101. राज्य सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं को बहु सेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से महज़ 4 (चार) प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी जिससे 50 (पचास) प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार इस परियोजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करेगी।

शहरी विकास

102. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के बावजूद प्रदेश की केवल 10 (दस) प्रतिशत जनसंख्या अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में रहती है। हमारी सरकार ने लगभग 15 वर्षों के अन्तराल के बाद तेजी से विकसित होते क्षेत्रों के नियोजित विकास की दृष्टि से 2020 में ऐसे क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया है तथा 3 (तीन) नए नगर निगमों क्रमशः मण्डी, पालमपुर एवं सोलन; एक नई नगर परिषद सरकाघाट; और, सात नई नगर पंचायतों क्रमशः शाहपुर, अम्ब, आनी, निरमण्ड, चिड़गाँव, नेरवा तथा कण्डाघाट का गठन किया।

103. नव गठित शहरी निकायों तथा नए शामिल क्षेत्रों में सरकार ने तीन वर्षों के लिए सम्पत्ति करों में छूट दे दी है

तथा उनके हक–हकूक भी सुरक्षित रखे गए हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाईट, पार्क, सड़कें, पार्किंग, ओपन जिम इत्यादि प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के मूलभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नवगठित शहरी निकायों को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक पद शीघ्र भरे जाएंगे।

104. 2021–22 में नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में शामिल नये क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए मूलभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को एक करोड़ रुपये प्रति नगर निगम दिया जाएगा। मैं प्रत्येक नवगठित नगर पंचायत को 20 (बीस) लाख रुपये अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

105. मैं घोषणा करता हूँ कि 2021–22 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को ODF+ स्तर पर प्रमाणित करवाया जाएगा। 15 (पन्द्रह) शहरी स्थानीय निकायों को ODF++ के रूप में प्रमाणित करवाने और इन्हें Star Rating of Garbage Free Cities-2021 के तहत एक स्टार के रूप में प्रमाणित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला, धर्मशाला और मण्डी को 5 स्टार के रूप में प्रमाणित करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

106. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार शिमला जल प्रबन्धन निगम के माध्यम से लगभग 94 (चौरानबे) करोड़ रुपये की लागत से पूरे होने वाले निम्न कार्यों को आगामी वर्ष में शिमला निवासियों को समर्पित करेगीः–

- लगभग 63 (तरेसठ) करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत होने वाले लालपानी, मल्याणा और ढली Sewage Treatment Plants.
- अश्वनी खड्ड पर लगभग 12 (बारह) करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला नया Sewage Treatment Plant.
- टुटू निवासियों के लिए 18 (अठारह) करोड़ रुपये से बनने वाला Sewer Network तथा Sewage Teatment Plant.
- लालपानी में 2.5 किलोलिटर प्रतिदिन क्षमता वाला Faecal (फीकल) Sludge Treatment Plant.

107. इसके अतिरिक्त शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में 24X7 जल वितरण प्रणाली स्थापित करने हेतु 270 (दो सौ सत्तर) करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य 2021–22 में आरम्भ कर दिया जाएगा।

108. धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत Root Zone Technology पर आधारित चार स्थानों पर Sewage Treatment Plants का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और STP का निर्माण कार्य 2021–22 में आरम्भ कर दिया जाएगा। धर्मशाला शहर में ही 10 (दस) करोड़ रुपये की लागत से एक Faecal (फीकल) Sludge and Septage Management Plant का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। 2021–22 में धर्मशाला शहर में 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये की लागत से 7 (सात) हज़ार LED Street Lights लगाई जाएंगी।

109. अध्यक्ष महोदय, शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत अनेक कार्य पूर्ण किये जाएंगे। जिनमें संजौली से IGMC का रास्ता, IGMC के पास बहुमंज़िला पार्किंग, शिमला सर्कुलर रोड को चौड़ा करना तथा इस पर पैदल मार्गों का निर्माण, रिज मैदान का Stabilization, अनेक स्थानों पर Foot Over Bridge तथा Escalators का निर्माण, बिजली उपभोक्ताओं के लिए Smart Meter, कृष्णानगर में स्मार्ट स्कूल का निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं। इनके कार्यान्वयन को गति देने के लिए लगभग 258 (दो सौ अड्ठावन) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

110. Ease of Doing Business सुधारों के अन्तर्गत ही योजना अनुमतियां अथवा भवनों के नक्शों की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु AutoDCR (Software) को शहरी निकायों एवं प्लानिंग क्षेत्रों में लागू किया जाएगा ताकि भवन मानचित्रों की जाँच स्वतः सॉफ्टवेयर द्वारा ही हो सके और मानव हस्तक्षेप कम हो।

111. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवा वितरण के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 163 (एक सौ तरेसठ) करोड़ रुपये और इसी प्रकार केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 161 (एक सौ इकसठ) करोड़ रुपये की अनुदान राशि शहरी स्थानीय

निकायों और छावनी बोर्डों को 2021–22 में प्रदान की जाएगी।

112. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों में Legacy Waste की समस्या को लेकर चिंतित है। वर्ष 2021–22 में इस समस्या के समाधान के लिए समुचित योजना बनेगी और विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

भू–प्रशासन एवं आपदा प्रबन्धन

113. राजस्व विभाग में नई NGDRS (National Generic Document Registration System) प्रणाली के माध्यम से सम्पत्ति के पंजीकरण का सरलीकरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने पंजीकरण कार्य को पायलट आधार पर आरम्भ किया था। अब विभाग प्रदेश के सभी 174 (एक सौ चौहत्तर) उप–पंजीकार कार्यालयों में इसे लागू करेगा। इससे पंजीकरण सुविधा ऑनलाईन प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगीं और नागरिकों को फीस देने, ई–स्टाम्प प्राप्त करने और पंजीकरण दस्तावेजों को घर से जमा कराने की सुविधा मिलेगी।

114. आपदा प्रबन्धन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु फ्रैंच डवेल्पमेंट एजेंसी (AFD) के साथ लगभग 800 (आठ सौ) करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा देश के आठ राज्यों में प्रस्तावित विश्व बैंक वित्त पोषित राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण योजना में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है।

115. 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से 2021–22 में 409 (चार सौ नौ) करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके तहत क्षमता निर्माण से आपदाओं का जोखिम कम किया जाएगा और प्रभावित लोगों को त्वरित राहत सुनिश्चित की जाएगी।

116. माननीय प्रधानमन्त्री के मार्गदर्शन के अनुसरण में मेरी सरकार ने राजस्व विभाग में पुराने अप्रचलित नियमों और विनियमों में संशोधन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो वर्तमान कानून और नियमों में उचित

संशोधनों एवम् राजस्व सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु अनुशंसा करेगी।

117. मैं राजस्व विभाग में कार्यरत अँशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह बढ़ाने तथा नम्बरदारों के मासिक मानदेय को 300 (तीन सौ) रुपये बढ़ाने की भी सहर्ष घोषणा करता हूँ।

पेयजल

118. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार केन्द्रीय बजट में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2021–22 के दौरान देशव्यापी परिव्ययों को बढ़ाकर 2,87,000 (दो लाख सत्तासी हजार) करोड़ रुपये करने तथा इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों को भी लाने के लिए केन्द्र सरकार का हार्दिक धन्यवाद करती है।

119. केन्द्र सरकार के 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेश के 17,03,626 (सत्रह लाख तीन हज़ार छः सौ छब्बीस) में से लगभग 13 (तेरह) लाख घरों को घरेलू नल कनेक्शन अब तक उपलब्ध करवाये गए हैं। 2021–22 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 (तीन) लाख और घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाएंगे। 2020–21 के दौरान तीन ज़िलों क्रमशः किन्नौर, लाहौल स्पिति और ऊना में सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये गए हैं। केन्द्रीय सहायता से 2021–22 में प्रदेश के तीन और जिलों क्रमशः सोलन, हमीरपुर तथा बिलासपुर में भी शत्–प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

120. आँशिक रूप से कवर ग्रामीण बस्तियां, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 55 (पच्चपन) लीटर प्रतिदिन से कम पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 740 (सात सौ चालीस) करोड़ रुपये का प्रस्ताव New Development Bank (NDB) द्वारा फण्डिंग हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 24 (चौबीस) पेयजल योजनाओं, जिनसे 3,154 (तीन हज़ार एक सौ चौवन) बस्तियां लाभान्वित होंगी, का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

121. 187 (एक सौ सत्तासी) पेयजल योजनाएं, जिनसे लगभग 77 हज़ार घर लाभान्वित होंगे, के लिए 903 (नौ सौ तीन) करोड़ रुपये के प्रस्ताव को ADB द्वारा अन्तिम रूप

दे दिया गया है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद इन योजनाओं का निर्माण निकट भविष्य में प्रारम्भ होने की संभावना है।

122. 2021–22 में विभिन्न उठाऊ पेयजल एवम् सिंचाई परियोजनाओं के संचालन हेतु बिजली भुगतान के लिए 604 (छः सौ चार) करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार का प्रयास है कि इस व्यय को कम किया जाए। पांवटा साहिब क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का निर्माण 2021–22 में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 (दस) ऐसी परियोजनायें चिन्हित की जाएंगी जहाँ बिजली की अत्यधिक खपत हो तथा वहाँ पम्पों को सौर ऊर्जा से चलाया जा सके।

123. लोगों को जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में नाममात्र शुल्क पर पेयजल के नमूनों की जाँच की सुविधा में विस्तार किया जाएगा जिसके लिए 9 (नौ) नई जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जाएंगी। पानी के बिलों के ऑनलाईन भुगतान तथा नए कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन हेतु Mobile App उपलब्ध करवाया जाएगा।

124. शहरी क्षेत्रों में नई मल निकासी योजनाओं का निर्माण व पहले से निर्मित मल शोधन संयन्त्रों के सुधारीकरण का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। शहरों से लगते 166 (एक सौ छयासठ) चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों को पहले से निर्मित मल शोधन संयन्त्रों से जोड़ा जाएगा। इन संयन्त्रों से शोधित जल को पुनः प्रयोग में लाने हेतु भी प्रयास किये जाएंगे। इस समय पायलट आधार पर 4 (चार) मल निकासी योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना को प्रदेश के अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

125. मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों – परवाणू, काला अम्ब, नालागढ़, बद्दी तथा ब्यास नदी पर कुल्लू, मनाली एवं मण्डी जिले के कुछ स्थानों – में Sewage Schemes तथा STPs का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 364 (तीन सौ चौंसठ) करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। 2021–22 में इन परियोजनाओं के लिए 200 (दो सौ) करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

126. अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी परियोजनाएं बनाने हेतु माननीय विधायकों से सुझाव आते रहे हैं। मैं माननीय विधायकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे विधायक प्राथमिकता निर्धारण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी परियोजनाओं के बारे विचार करें। ये योजनाएं भी नाबार्ड से funding की पात्र हैं।

127. मैं जल गार्डों, पैरा फिटर्ज़ और पम्प ऑपरेटर्ज़ के मानदेय में 300 (तीन सौ) रुपये प्रति माह बढ़ौतरी करने की घोषणा करता हूँ।

उद्योग/ निजी निवेश

128. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना समय की आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए कदमों के फलस्वरूप निजी निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में अब पहले से काफी कम समय लगता है। हम इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

129. 2019 में प्रदेश सरकार ने Global Investor Meet का आयोजन किया था जिसमें प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने धर्मशाला आए थे। लगभग 96,000 (छियानबे हज़ार) करोड़ रुपये के 700 (सात सौ) से अधिक समझौता ज्ञापन इस इन्वेस्टर मीट में हस्ताक्षरित किये गए थे। एक महीने के अन्दर ही दिसम्बर, 2019 में माननीय गृह मन्त्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में हमने लगभग 13,000 (तेरह हज़ार) करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन की पहली ग्राऊंड ब्रेकिंग की थी। कोरोना के विकट दौर में व्यवधान आये फिर भी हम कम से कम 10,000 (दस हज़ार) करोड़ रुपये की दूसरी ग्राऊंड ब्रेकिंग के लिए पूर्णतः तैयार हैं। सच बात तो यह है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार महत्वकाँक्षी तथा सुनियोजित तरीके से प्रदेश में निजी निवेश आमन्त्रित करने का बीड़ा उठाया है। हम प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा किः–

मेरी मंज़िल मेरे करीब है,
इसका मुझे अहसास है।
गुमां नहीं मुझे इरादों पर अपने,
ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है।।

130. विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने की कड़ी में केन्द्र सरकार को निम्न प्रस्ताव भेजे गये हैं जिनके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हैः–

- ऊना ज़िला में 1,405 (एक हज़ार चार सौ पाँच) एकड़ भूमि पर 1,190 (एक हज़ार एक सौ नब्बे) करोड़ रुपये की Bulk Drug Park (बल्क ड्रग पार्क) परियोजना। इससे 8,000 (आठ हज़ार) करोड़ रुपये का निवेश, 50,000 (पचास हज़ार) करोड़ रुपये का टर्न ओवर तथा 15,000 (पन्द्रह हज़ार) रोज़गार सृजन अपेक्षित हैं। केन्द्र सरकार से इस पार्क के लिए 1,000 (एक हज़ार) करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।

- नालागढ़ में 265 (दो सौ पैंसठ) एकड़ भूमि पर 261(दो सौ इकसठ) करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले Medical Devices Park (मेडिकल डिवाईसिज़ पार्क) की स्थापना। इसकी स्थापना से लगभग 3 से 5 (तीन से पाँच) हज़ार करोड़ रुपये का निवेश तथा 20,000 (बीस हज़ार) करोड़ रुपये का टर्न ओवर व 10,000 (दस हज़ार) लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

- नालागढ़ में 100 (सौ) एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क।

- नालागढ़ में लगभग 400 (चार सौ) एकड़ भूमि पर एक Electronics Manufacturing Hub (इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग हब) तथा एक Power Equipment Manufacturing Hub (पावर इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरिंग हब)।

131. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रोज़गार सृजन के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। माननीय सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि आज के परिवेश में निजी निवेश एवम् स्वरोज़गार के बिना अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति नहीं दी जा सकती। यह भी आवश्यक है कि हम रोज़गार के सन्दर्भ में एक नये Eco-system को प्रोत्साहित करें जिसमें प्रदेश के युवा नौकरियों के सृजक बनें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये

मेरी सरकार ने 'मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना' 2018–19 में आरम्भ की है।

132. मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत अब तक 3 (तीन) हज़ार से अधिक प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनके माध्यम से लगभग 10 (दस) हज़ार रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। योजना को अब ऑनलाईन किया गया है। अनुदान राशि के 60 प्रतिशत भाग की फ्रंट लोडिंग का प्रावधान भी कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मैं अब परियोजना लागत की वर्तमान 60 (साठ) लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 (एक) करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही पात्र प्लांट व मशीनरी की सीमा, जिस पर अनुदान दिया जाता है, को वर्तमान 40 (चालीस) लाख रुपये से बढ़ाकर 60 (साठ) लाख रुपये करने का भी मैं प्रस्ताव करता हूँ।

133. आगामी वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत गतिविधियों का और विस्तार किया जाएगा जिसके लिए सरकार अविलम्ब एक कमेटी गठित करेगी व तीन माह के भीतर योजना के नये स्वरूप को लोकार्पित किया जाएगा। इस योजना पर 2021–22 में 100 (सौ) करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

134. आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises योजना आरम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य आधारित असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान कर संगठित क्षेत्र में लाना है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा 'एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 12 ज़िलों के लिए, वहाँ की संभावनाओं के अनुरूप, एक–एक उत्पाद स्वीकृत कर दिया गया है।

135. भारत सरकार खिलौना निर्माण उद्योग के विकास पर बल दे रही है। इस सैक्टर को प्रदेश में विकसित करने के लिए मैं प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। उद्योग विभाग तथा राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प निगम के सहयोग से 2 कलस्टर 2021–22 में स्थापित किये जाएंगे। काँगड़ा स्थित 'भारतीय फैशन तकनीक संस्थान' की विशेषज्ञ सेवाएं भी इसके लिए ली जाएंगी।

136. बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विकास प्राधिकरण का हिमाचल के विकास में विशेष महत्व है। निवेशकों की आवश्यकता को देखते हुए पिंजौर से नालागढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग की फोरलेनिंग के लिए भू–अधिग्रहण हेतु 15(पन्द्रह) करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए इसी वर्ष झाड़माजरी में बाल्द खड्ड पर बनने वाला पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

137. BBN तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत ढाँचा विकास का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में पुलिस ढाँचे का विस्तार किया जाएगा। BBN में उपलब्ध भूमि पर नई Township विकसित करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

ऊर्जा/ बहुउद्देशीय परियोजनाएं

138. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी जलविद्युत उत्पादक राज्य है। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि समस्त पन विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में शामिल किया गया है।

139. सरकार ने लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निर्माणकर्ताओं को एक मुश्त रियायत प्रदान करने का निर्णय नवम्बर, 2020 में लिया है। 2021–22 में लगभग 755 (सात सौ पचपन) मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना है जिनमें क्रमशः बजोली होली (180 मेगावाट), पार्वती–II (400 मेगावाट), टिडोंग–I (150 मेगावाट) और लम्बाडग (25 मेगावाट) सम्मिलित हैं।

140. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हाइड्रो पॉवर पॉलिसी–2006 में लाई गई थी। हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आये बदलावों के दृष्टिगत् तथा इस क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए b| o"kZ ß**स्वर्ण जयन्ती ऊर्जा नीति"** प्रस्तुत करेगी। इस नीति में हाईब्रिड पॉवर प्रोजेक्टस भी सम्मिलित होंगे। साथ ही हम एक ऊर्जा दृष्टि पत्र (Power Vision Document) 2030 भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें 2030 तक 10 (दस) हज़ार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का दोहन Renewal Energy के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।

141. आगामी वर्ष Plug & Play Model के तहत लगभग 10 (दस) परियोजनाओं की स्वीकृतियां प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा आवंटित की जाएंगी।

142. सरकार सभी उपभोक्तताओं को विश्वसनीय और 24 x 7 विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसी दिशा में 2021–22 में 8 (आठ) योजनाओं पर चल रहे काम को गति दी जाएगी तथा 5 (पाँच) नई Extra High Voltage योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इनसे 417 MVA की क्षमता का संवर्धन होगा।

143. बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2021–22 में 29 (उनतीस) नई योजनाएं शुरु की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कार्यान्वित अन्य 23 (तेईस) योजनाओं को भी वित्त वर्ष 2021–22 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

144. कम वोल्टेज़ की समस्या को खत्म करने के लिए एक बृहद् योजना कार्यान्वयन के अन्तिम चरण में है। तत्पश्चात् राज्य में कम वोल्टेज की समस्या से ग्रस्त अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा और यदि कोई क्षेत्र रह गया है तो उसे दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा।

145. विद्युत आपूर्ति की Real Time Monitoring के लिए ऑनलाईन व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिससे कि आपूर्ति एवं वोल्टेज़ सम्बन्धी समस्याओं की तुरन्त सूचना मिल सकेगी। इससे इन समस्याओं का शीघ्र निवारण होगा।

146. 2021–22 में सभी electro-mechanical (इलैक्ट्रो –मेकैनिकल) मीटरों को बदल कर electronic (इलैक्ट्रॉनिक) मीटर लगा दिए जाएंगे।

147. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड Aggregate Technical and Commercial Losses को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। 2024–25 तक इन losses को एकल अंक में लाया जाएगा।

148. पांगी, लाहौल एवं स्पिति क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अगले वर्ष इन क्षेत्रों में लघु

जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

149. पांगी तथा लाहौल–स्पिति में 2021–22 में 1,500 (एक हज़ार पाँच सौ) BPL परिवारों के घरों में 250 (दो सौ पचास) वाट क्षमता प्रति घर Off-grid सौर पॉवर संयन्त्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

150. 13 (तेरह) शहरों के विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। योजना में SCADA System, स्वचालन तथा वर्तमान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया जाएगा। योजना को आगामी 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

151. 2021–22 में HP Clean Energy Transmission Investment Programme के अन्तर्गत 1,314 (एक हज़ार तीन सौ चौदह) MVA की परिवर्तन क्षमता के 10 (दस) नए सब–स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क में 454 (चार सौ चौवन) सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाईनों का निर्माण भी किया जाएगा। इन कार्यों पर 413 (चार सौ तेरह) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। ये योजनाएं रावी, ब्यास, पब्बर और सतलुज बेसिन में हाइड्रो पॉवर की निकासी तथा Intra State Transmission System के सुदृढ़ीकरण के साथ बिजली की विश्वसनीयता बढ़ायेंगी। सभी EHV सब–स्टेशनों की रिमोट मॉनिटरिंग के लिए 2021–22 में Joint Command Centre का निर्माण किया जाएगा।

152. मैं घोषणा करता हूँ कि 'ग्रीन गौशाला' अवधारणा के अनुरूप 2021–22 में 5 (पाँच) बड़ी गौशालाओं को 'हरित और आत्मनिर्भर' बनाने के लिए अपनाया जाएगा।

153. मेरी सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा एवं शिक्षा संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से ग्रिड से जुड़े Roof Top सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। 2021–22 में इसके अन्तर्गत 2 (दो) मैगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यटन

154. पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को राहत देने के लिए Interest Subvention Scheme चल रही है। सभी हितधारकों से चर्चा करके इस योजना में आवश्यक सुधार तथा संशोधन किये जाएंगे जिससे यह योजना पर्यटन से

जुड़े अधिकाँश वर्गों तक पहुँच सके। माँग के अनुसार इस योजना में समुचित बजट प्रावधान किया जाएगा।

155. हम एक लम्बे समय से सुनते आ रहे हैं कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह सच है परन्तु यह भी सत्य है कि इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस सोच और विश्वास की आवश्यकता थी उसकी कमी रही। यही कारण है कि हम वर्षों तक प्रदेश में नए पर्यटक स्थलों का विकास नहीं कर पाये। हमारी सरकार ने 'नई राहें–नई मंज़िलें' योजना बना कर पर्यटन विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। यहां यह कहना उचित रहेगा किः–

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा।

156. **'नई राहें–नई मंज़िलें'** योजना को विस्तार देते हुए और उसमें नये आयाम जोड़ते हुए मैं 2021–22 में निम्न योजनाओं को कार्यरूप देने की घोषणा करता हूँः–

- माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा 3 अक्तूबर, 2020 को अटल टनल, रोहतांग देश को समर्पित करने के तुरन्त बाद से लाहौल में पर्यटकों की आमद में अभूतपूर्व बढ़ौतरी देखी जा रही है। अटल टनल के दोनों ओर प्रतिकूल और अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।
- अटल सुरंग देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए, जून–2021 से पहले, पार्किंग, Wayside Amenities, हिमाचली हस्तशिल्प एवं परम्परागत उत्पादों का बिक्री केन्द्र एवम् यथा सम्भव ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
- ग्रामीण पर्यटन को बल देने के लिए 2021–22 में, पहले चरण में 15 (पन्द्रह) स्थानों को, गैर जन–जातीय जिलों में एक–एक तथा प्रत्येक जन–जातीय विकास परियोजना क्षेत्र में एक–एक स्थान को, पर्यटक आकर्षण हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य को स्थानीय भागीदारी से

किया जाएगा जिससे क्षेत्र के युवाओं तथा महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर मिलेंगे।

- चुनी हुई सड़कों को व्यवस्थित तथा चरणबद्ध तरीके से 'पर्यटक सड़क' के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सड़कों पर निजी भागीदारी से tourist friendly infrastructure (टूरिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर) बनाया जाएगा।
- साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए चिन्हित मार्गों को साइक्लिंग रूट के रूप में प्रचारित करने के लिए वर्ष भर में पहाड़ी सड़कों पर cycling expedition आयोजित किये जाएंगे।
- प्रदेश में HPTDC के एक होटल में 'आयुर्वेदिक वैलनेस केन्द्र' तथा एक होटल को 'डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन' में रूप में विकसित किया जाएगा।

157. लाहौल स्पिति को ईको टूरिज़्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहल करते हुए 2021–22 में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:–

- सिस्सू में पर्यटक सूचना केन्द्र तथा कला, संस्कृति और साहसिक खेल केन्द्र का निर्माण।
- उदयपुर, जिस्पा और काज़ा में way side सुविधाओं का निर्माण।
- लाहौल में नई स्कीईंग साईट का चयन।
- लाहौल में आईस स्केटिंग रिंक स्थापित किया जाएगा।
- स्पिति में आईस हॉकी को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- लाहौल स्पिति के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षण।

158. पर्यटन के लिए नए आकर्षण तैयार करने के लिए वर्ष 2019–20 में मैंने मण्डी में 'शिव धाम' पर्यटन स्थल स्थापित करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में इसके दूसरे चरण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें 12 (बारह) ज्योर्तिलिंग, प्रशासनिक भवन, सड़क, पार्किंग आदि

सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 150 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। 2021–22 में 40 (चालीस) करोड़ रुपये का व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

159. सभी इच्छुक होम स्टे इकाईयों को प्रचार–प्रसार और ऑनलाईन बुकिंग सुविधा के लिए HPTDC तथा पर्यटन विभाग की वेबसाईट से जोड़ा जाएगा।

160. मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि बहुप्रतीक्षित धर्मशाला–मेकलोडगंज रोप–वे आगामी वर्ष में आने वाले tourist season से पहले ही पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धर्मशाला शहर के समीप सरकारी भूमि उपलब्ध है जिस पर निजी पर्यटक बसों के लिए पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा।

161. युवाओं को पर्यटन से जोड़ने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एक हज़ार युवाओं को टूरिस्ट गाईड, पर्वतारोहरण, साहसिक खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यटन में निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।

162. पर्यटन को कोविड–19 से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए एक Multi Media Publicity Campaign चलाया जाएगा जिसमें स्थानीय आकर्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

163. मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि 2021–22 में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 218 (दो सौ अठारह) करोड़ रुपये की लागत से बन रही निम्न परियोजनायें जनता को समर्पित कर दी जाएंगीः–

- ✓ सांस्कृतिक केन्द्र बड़ागांव, मनाली।
- ✓ सांस्कृतिक केन्द्र, जंजैहली।
- ✓ विजय हाई स्कूल, मण्डी का जीर्णोद्धार।
- ✓ Convention Centre मण्डी, धर्मशाला तथा क्यारीघाट।
- ✓ पार्किंग, ज्वालामुखी।
- ✓ चामुण्डा मन्दिर परिसर, काँगड़ा का जीर्णोद्धार।
- ✓ बैंटनी कैसल, शिमला का जीर्णोद्धार।
- ✓ Art and Craft सेंटर, काँगड़ा।

- ✓ Artificial Climbing Wall, मनाली।
- ✓ लाईट एण्ड साऊंड शो, शिमला।
- ✓ Art and Craft Centre भलेई माता, चम्बा।
- ✓ पैराग्लाईडिंग सेंटर, बीड़ बिलिंग।
- ✓ हाटेश्वरी मन्दिर सौंदर्यकरण, हाटकोटी शिमला।
- ✓ शिमला, कांगनीधार, रामपुर और बद्दी में हैलिपोर्ट।

मंज़िल पर सफलता का निशान चाहिए,
होंठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए,
बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से,
हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए।

श्रम एवं रोजगार

164. अध्यक्ष महोदय, कोरोना में Building and other Construction Workers Welfare Board ने श्रमिकों को राहत पहुँचाने में सहयोग दिया है। निश्चित समयावधि पूरी करने वाले मनरेगा कर्मियों को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ है। बोर्ड आगामी वर्ष में अपनी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करेगा एवम् पात्र व्यक्तियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य–योजना बनाएगा।

165. हमारी सरकार ने Ease of Doing Business में बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इस श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश दिहाड़ी नियम जारी किये जाएंगे।

166. कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना–2018 के अन्तर्गत प्रदेश के युवा अब अपना पंजीकरण ऑनलाईन करवा सकेंगे। इन अभ्यार्थियों के लिए Counselling Programme भी शुरु किया जाएगा। मेरी सरकार इन भत्तों पर 100 (सौ) करोड़ रुपये खर्च करेगी।

167. रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 (सात हज़ार) लोगों को निजी उद्योगों में नियुक्तियां दिलवाई जाएंगी।

परिवहन

168. मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि नीति आयोग ने 'इलैक्ट्रिक वाहन नीति' बनाने के लिए प्रदेश को Light House State के रूप में चयनित किया है जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

169. हमारी सरकार सड़क सुरक्षा के लिए और मोटर वाहन नियमों के पालन हेतु 2021–22 में अनेक कदम

उठाएगी जिनका विवरण मैं माननीय सदन से सांझा करना चाहूँगाः–

- यात्री एवं माल भार कर का प्रशासनिक नियन्त्रण परिवहन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो वाहन सम्बन्धी समस्त करों का युक्तिकरण कर इन्हें 'एकल मोटर वाहन कर' व्यवस्था के तहत लाएगा। इस व्यवस्था से वाहन मालिक एक ही स्थान पर कर का भुगतान कर पाएंगे।
- PPP मोड पर राज्य में चयनित स्थानों पर वाहनों की फिटनेस के लिए 6 (छः) मोबाइल स्वचालित परीक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।
- आधुनिक तकनीक युक्त ई–चालान प्रणाली शुरु की जाएगी जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी।
- चालकों को गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने, ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के लिए ज़िला बिलासपुर, सोलन, मण्डी और काँगड़ा में आधुनिक सुविधायुक्त ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक स्थापित किये जाएंगे।
- महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार सार्वजनिक यात्री वाहनों के location tracking device (लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) और panic button प्रणाली को कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर से जोड़ेगी।

170. केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नई सड़कों के नेटवर्क का विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बस सेवा की माँग बढ़ रही है। मैं "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार (परिवहन) योजना" शुरु करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के तहत उन वाहन योग्य सड़कों पर, जहाँ बसों का संचालन नहीं है, वहाँ 18 (अट्ठारह) सीटों तक के छोटे वाहन चलाये जाएंगे। मेरी सरकार इस योजना के तहत बेरोज़गार युवक एवं युवतियों को सभी चिन्हित मार्गों पर रियायती कर दरों पर परमिट देने का प्रावधान करेगी।

171. परिवहन निगम को सुदृढ़ करने के लिए मैं 2021–22 में पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 (दो सौ) नई बसें खरीदने की घोषणा करता हूँ।

172. परिवहन निगम को बस स्टैंड और कर्मशालाओं में बेहतर सुविधायें प्रदान करने एवम् उनके रख–रखाव के लिए 15 (पन्द्रह) करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव करता हूँ।

173. परिवहन निगम की क्षेत्रीय कर्मशाला, धर्मशाला; तथा शिमला के ढली और लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करने का कार्य 2021–22 में शुरु किया जाएगा।

परिवहन निगम को 2021–22 में 377 (तीन सौ सतहत्तर) करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सड़क परिवहन

174. अध्यक्ष महोदय, देश के पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरम्भ की गई महत्वकाँक्षी 'प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना' हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हुई है। अब तक प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश भर में 17,716 (सत्रह हज़ार सात सौ सोलह) किलोमीटर लम्बे 2,896 (दो हज़ार आठ सौ छयानवे) सड़क कार्य पूरे किये गए हैं। इन कार्यों पर कुल 5,378 (पाँच हजार तीन सौ अठहत्तर) करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये शेष 2,756 (दो हजार सात सौ छप्पन) करोड़ रुपये की लागत से 787 कार्यों, जिनकी कुल लम्बाई 4,143 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत् प्रदेश में सड़कों के जाल में इतना विस्तार सम्भव नहीं था। मैं कृतज्ञ हिमाचल प्रदेश की ओर से श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिमाचल के प्रति स्नेह का स्मरण करता हूँ।

उनकी कविता की ये पंक्तियां हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैंः–

धरती को बौनों की नहीं,
ऊँचे कद के इन्सानों की ज़रूरत है।
इतने ऊँचे कि आसमान छू लें,
नये नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बो लें।

175. 2021–22 में प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना–III के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति मिलते ही 3,125

(तीन हजार एक सौ पच्चीस) किलो मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

176. Output and Performance Based Maintenance Contract (OPBMC) / Performance Based Maintenance Contract (PBMC) के तहत बेहतर सतह और गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने हेतु हर मण्डल में काम किया जाएगा जिसके तहत 2021–22 में 5,000 (पाँच हज़ार) किलोमीटर सड़कें ठीक की जाएंगी।

177. सैंज–लुहरी–औट नेशनल हाईवे पर all weather connectivity प्रदान करने के लिए जलोड़ी पास के नीचे 4 किलोमीटर लम्बाई की डबल लेन सुरंग की DPR को अन्तिम रूप दिया जाएगा। दूरी और यात्रा को कम करने के लिए सुरंगों के निर्माण और सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर लम्बे पुलों के निर्माण की संभावना तलाशने के लिए feasibility study प्रस्तावित है।

178. Green National Highway के अन्तर्गत 2021–22 में 105 (एक सौ पाँच) किलोमीटर लम्बी पांवटा साहिब–गुम्मा–फीडस पुल की निविदाओं को अन्तिम रूप दे कर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा तथा इसके साथ ही 110 (एक सौ दस) किलोमीटर लम्बी हमीरपुर–मण्डी सड़क हेतु भू–अधिग्रहण के लिए अवार्ड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

179. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 5 (पाँच) राष्ट्रीय राजमार्गों के 785 (सात सौ पचासी) किलोमीटर के 4 (चार) लेनिंग का कार्य शुरु कर दिया गया है। शिमला–मटौर रोड प्रोजेक्ट के लिए ज्वालामुखी से काँगड़ा सेक्शन तक, पठानकोट – चक्की – मण्डी सड़क के प्रथम पैकेज पंजाब– हिमाचल बॉर्डर से सिहूनी सैक्शन के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

180. 2021–22 में कीरतपुर–नेरचौक पर 31 (इकतीस) किलोमीटर और टकोली–कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 30 (तीस) किलोमीटर four laning का कार्य पूरा कर लिया जाएगा जिससे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्ग पर आवाजाही बेहतर हो सकेगी।

181. अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट भाषण में मैंने अपनी सरकार का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया था कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को सड़क से जोड़ा जाएगा। इनके बारे में हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

- 2020–21 के प्रारम्भ में सड़क से वंचित पंचायतें–87 (सत्तासी)
- वर्ष के दौरान सड़क से जोड़ी गई पंचायतें–29 (उनतीस)
- पंचायतें जिनके लिए परियोजना स्वीकृत की गई, जो 2023–24 तक सड़क से जोड़ दी जाएंगी–33 (तैंतीस)
- अन्य पंचायतें जो जीप योग्य सड़क से जुड़ी हुई हैं–15 (पन्द्रह)
- पंचायतें जहां भूमि के अभाव, वन क्षेत्र इत्यादि के मसले के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया–10(दस)

182. इस वर्ष कई नई पंचायतों का गठन किया गया है जिसमें से कुछ पंचायतें सड़क विहीन हो सकती हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसी नवगठित पंचायतों और पहले की शेष बची 10 (दस) पंचायतों को भी समयबद्ध विस्तृत योजना बनाकर सड़क से जोड़ा जाएगा।

183. हमारी सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 641 (छः सौ इकतालीस) करोड़ रुपये के 27 (सत्ताईस) कार्यों का शैल्फ केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति मिलते ही इन सड़कों पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

184. विश्व बैंक की सहायता से हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना में तीन चरणों में 650(छः सौ पचास) किलोमीटर लम्बी सड़कों का मध्यवर्ती अथवा डबल लेन में उन्नयन किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत 1,350 (एक हज़ार तीन सौ पचास) किलोमीटर लम्बी सड़कों का रख–रखाव व सुधार किया जाएगा। परियोजना का ट्रांच–1 जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रथम चरण में बरोटीवाला – बद्दी – साई – रामशहर सड़क, दधोल – लदरौर सड़क, रघुनाथपुरा – मण्डी – हरपुरा –

भराड़ी सड़क, मण्डी – रिवालसर – कलखर सड़क को मध्यवर्ती अथवा डबल लेन में उन्नयन किया जाएगा।

185. 'मुख्य मन्त्री ग्राम सड़क योजना' के अन्तर्गत 75 (पचहत्तर) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। इससे छूटे हुए गांव व बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

186. सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने एवम् अधिकाँश सड़कों को वर्ष भर अच्छी हालत में रखने के लिए preventive maintenance के तहत Micro Surfacing, Bitumen Slurry और Fog Seal तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

187. सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50 (पचास) करोड़ रुपये की लागत से 140 (एक सौ चालीस) किलोमीटर सड़कों पर W-Metal बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। भविष्य में नाबार्ड और PMGSY में W-Metal क्रैश बैरियर भी प्रस्तावित किये जाएंगे।

188. HP Road and Infrastructure Development Corporation (HPRIDC) शहरी सड़क सुधार हेतु Urban Road Improvement Plan पर कार्य करेगा जिसके लिए 8 जिलों बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, सिरमौर और ऊना को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना में सड़कों का उन्नयन, Bye Pass निर्माण, गलियों का सौंदर्यकरण, जंक्शन सुधार इत्यादि पर काम किया जाएगा।

189. 2021–22 में 'स्वर्ण जयन्ती ग्रीन बिल्डिंग पहल' को GRIHA काऊंसिल के साथ शुरु किया जाएगा जो देश की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग बॉडी है जिससे राज्य में 200 (दो सौ) सरकारी भवनों को GRIHA रेटिंग सिस्टम पर रेट किया जाएगा। इसी के साथ ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के सहयोग से चिन्हित भवनों में प्रकाश, ताप और शीतलन उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

190. सड़क निर्माण तकनीक में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के दृष्टिगत् लोक निर्माण विभाग का युक्तिकरण तथा पुनर्गठन किया जाएगा जिससे इस विभाग की कार्यशैली को और प्रभावी बनाया जा सके।

191. सड़क निर्माण की लम्बी यात्रा में प्रदेश नये आयाम स्थापित करने के कगार पर है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश

38,470 (अड़तीस हज़ार चार सौ सत्तर) किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कें हैं। 2022 तक इसे 40 (चालीस) हज़ार किलोमीटर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध लगभग 30,244 (तीस हज़ार दो सौ चौवालीस) किलोमीटर ब्लैक टॉप युक्त सड़कों को 2022 तक बढ़ा कर 34 (चौंतीस) हज़ार किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है।

192. प्रदेश में सड़क सम्पर्क मार्गों में अभूतपूर्व बढ़ौतरी को देखते हुए उनके रख–रखाव के लिये नई पहल करने की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय युवाओं की भी भागीदारी हो। इसके लिये मैं 5,000 (पाँच हजार) युवाओं को सड़कों के रख–रखाव तथा अन्य विभागीय कार्यों के लिये Part Time Multi Task Workers के तौर पर लगाये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

193. अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं सड़क एवम् पुलों के निर्माण से सम्बन्धित 2021–22 के लिये निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तुत करता हूँः–

- ❖ मैटलिंग एण्ड टॉरिंग–2,000 (दो हज़ार) किलोमीटर
- ❖ वाहन योग्य सड़कों का निर्माण–1,000 (एक हज़ार) किलोमीटर
- ❖ क्रॉस ड्रेनेज–945 (नौ सौ पैंतालीस) किलोमीटर सड़कों पर
- ❖ पुलों का निर्माण–80 (अस्सी)
- ❖ सड़क सुविधा से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या–90 (नब्बे)
- ❖ सड़कों का उन्नयन–800 (आठ सौ) किलोमीटर
- ❖ आवधिक नवीनीकरण–2,200 (दो हजार दो सौ) किलोमीटर

लोक निर्माण विभाग को 2021–22 के दौरान 4,502 (चार हजार पाँच सौ दो) करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

राज्य कराधान एवं आबकारी

194. हमारी सरकार कराधान एवं आबकारी हितधारकों, विशेष रूप से व्यवसायिक समुदाय से सीधा संवाद स्थापित करने हेतु 'Tax Haat' कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी। व्यापारियों

की समस्याओं के निराकरण हेतु Traders Facilitation Cell की भी स्थापना की जाएगी।

195. बेहतर प्रबन्धन के लिए मैं राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग के GST और आबकारी विंग के पुनर्गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

196. अध्यक्ष महोदय, विश्व के कई देशों में तथा भारत के कुछ राज्यों में Commercial Hemp Cultivation को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर नियन्त्रित किया जाता है। इससे निवेश एवम् रोजगार का सृजन होता है। राज्य सरकार प्रभावी नियामक व्यवस्था के अन्तर्गत Commercial Hemp की खेती की अनुमति देने के लिए एक नीति बनाएगी।

भाषा, कला एवं संस्कृति

197. मैं मेलों को दी जाने वाली सहायता को बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों को 3 लाख रुपये के स्थान पर 5 (पाँच) लाख रुपये, राष्ट्रीय स्तरीय मेलों को 2 (दो) लाख रुपये के स्थान पर 3 (तीन) लाख रुपये, राज्य स्तरीय मेलों को 1 (एक) लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये दिये जाएंगे।

198. अगले वर्ष आयोजित होने वाले सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों में एक दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व के 51वे (इक्यावनवे) वर्ष से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए समर्पित होगा।

199. जिला चम्बा, काँगड़ा, मण्डी व शिमला में ग्राम शिल्प मेलों का आयोजन किया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

200. अध्यक्ष महोदय, खेल युवाओं के शारीरिक एवम् बौद्धिक विकास का आधार हैं। स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं का होना न केवल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करता है बल्कि उन्हें व्यस्नों से भी दूर रखता है। हमारी सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।

मैं प्रदेश के युवाओं का इन पंक्तियों के साथ आह्वान करता हूँः–

जब हौसला कर लिया ऊँची उड़ान का,
फिर देख फिजूल है कद आसमान का।

201. मैं ग्राम पंचायतों के चुने हुये प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे 15वें वित्तायोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग पंचायतों में Open Air Gym तथा Re-creation Centre बनाने में भी करें।

202. खेल प्रशिक्षण में सुधार आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुसंगत प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जाएगी। खेल स्पर्धाओं के लिए ऑफ सीज़न (off-season) और समर सीज़न (summer season) खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाएंगे।

203. खेल के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 'मुख्यमन्त्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना' इस वर्ष भी जारी रहेगी और इस पर 10.22 करोड़ (दस करोड़ बाईस लाख) रुपये खर्च किये जाएंगे।

204. दत्तनगर, बिलासपुर और कण्डाघाट में निर्माणाधीन तीन खेल बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को इसी वर्ष शुरु कर दिया जाएगा जिसमें वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, एथलैटिक्स, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

205. 2021–22 में 14.50 करोड़ (चौदह करोड़ पचास लाख) रुपये की लागत से सुन्दरनगर और सोलन में इण्डोर स्टेडियम तथा माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नुरपूर, चम्बा और जंजैहली में इन्डोर खेल परिसरों का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास एवं कमजोर वर्गों का कल्याण

206. अध्यक्ष महोदय, बेटियां हमारे समाज एवं राज्य की गरिमा हैं। प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं, जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में बेटी को समानता और सम्मान का स्थान दिलाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार लिंग अनुपात को अधिक अनुकूल बनाने के लिये भी प्रयासरत है।

207. वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को दो लड़कियों तक 12 (बारह) हज़ार रुपये की Post Birth ग्रांट दी जा रही है। इन्हें छात्रवृति भी मिलती है। युक्तिकरण के सिद्धांत के आधार पर इन दोनों सहायताओं को एकीकृत करके मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब 21 (इक्कीस) हज़ार रुपये की Post Birth ग्रांट, फिक्स डिपोजिट

के रूप, में बेटी के जन्म पर ही दे दी जाएगी। यह लड़कियों को स्वावलम्बी बनने में सहायता करेगी।

208. बेटियों के जीवन में विवाह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन ले कर आता है। समाज की परम्परा और व्यवस्था के अनुरूप वे अपना घर छोड़कर अपने पति के घर परिवार को अपनाती हैं। यह आवश्यक है कि बेटियां स्वयं को कमज़ोर न समझें और उनके अभिभावक, परिवार के सदस्य और समाज उनके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनायें। 2021–22 से मैं "शगुन" नाम से नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जन–जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 (इकतीस) हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर वर्ष में 50 (पचास) करोड़ रुपये के व्यय प्रस्तावित हैं।

209. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए इसमें अभूतपूर्व विस्तार किया है। 2017–18 में 410 (चार सौ दस) करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय किये जाते थे। उस समय 4,13,000 (चार लाख तेरह हज़ार) लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही थी। वर्तमान में 5,77,000 (पाँच लाख सतहत्तर हज़ार) लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है जिस पर राज्य सरकार 875 (आठ सौ पच्चहत्तर) करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय कर रही है।

210. मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि 2021–22 में 40,000 (चालीस हज़ार) अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी जिस पर 60 (साठ) करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

211. अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और देखभाल सभ्य समाज का परिचायक है। हमारा अस्तित्व हमारे बुजुर्गों के कारण ही है, हम उनके ऋणी हैं। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उन्हें आर्थिक कठिनाईयों से न जूझना पड़े।

212. अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना "स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना" शुरु करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत 65 (पैंसठ)

वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 (एक हज़ार) रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 60,000 (साठ हज़ार) महिलायें लाभान्वित होंगी जिस पर 55 (पचपन) करोड़ रुपये खर्च होंगे।

213. वृद्धावस्था पेंशन का यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की पेंशन न मिल रही हो अथवा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध न रखते हों ताकि पेंशन योजना का लाभ ज़रूरतमंदों को मिले। इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे।

214. उपर्युक्त निर्णयों से अब लगभग 6.60 लाख (छः लाख साठ हज़ार) लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। इस बजट में घोषित योजनाओं के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सरकार 1,050 (एक हज़ार पचास) करोड़ रुपये खर्च करेगी जो कि 2017 के मुकाबले ढाई गुना है।

215. पिछले वर्ष हमारी सरकार द्वारा 'अटल पेंशन योजना' के अन्तर्गत असंगठित वर्ग के अँशदायियों को सरकार की ओर से दिये जाने वाले 50 प्रतिशत अँशदान, अधिकतम 2 (दो) हज़ार रुपये तक, को 31–3–2021 तक बढ़ाया गया था। वर्तमान लाभार्थियों और नये लोगों को अटल पेंशन योजना के लाभ को मैं सहर्ष 31–3–2022 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। योजना के लिए 15 (पन्द्रह) करोड़ रुपये रखे जाने प्रस्तावित हैं।

216. प्रदेश सरकार कामकाजी महिलाओं के बच्चों को डे–केयर सुविधा प्रदान करने के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व जन–भागीदारी से ज़िला मुख्यालयों पर क्रैच सुविधाओं को प्रोत्साहित करेगी।

217. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए मशोबरा में आगामी वर्ष में Pay and Stay आधार पर आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम खोला जाएगा।

218. अध्यक्ष महोदय, मैं आँगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को 500 (तीन सौ) रुपये प्रति माह,

मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 300 (तीन सौ) रुपये प्रति माह तथा आँगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को 300 (तीन सौ) रुपये प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

219. स्पष्ट है कि हमारी सरकार समाज के सभी ज़रूरतमन्द वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृतसंकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ताकत आवाज़ में नहीं विचारों में होनी चाहिए और विचारों की मंगलकामना को मूर्त रूप देने के लिए हिम्मत और हौसला होना चाहिए।

रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज़्बा,
वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते।

जन–जातीय विकास

220. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पूरे देश में आदर्श के रूप में माने जाते हैं। इनके निरन्तर विकास के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से लाहौल में प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा।

221. काज़ा में इंडोर स्टेडियम को उच्च पर्वतीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

222. केलंग में एंटी फ्रीज़ वाटर सप्लाई सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों का जीवन सरल हो तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।

223. 50वें पूर्ण राज्यत्व वर्ष के उपलक्ष पर राष्ट्रीय जन–जातीय उत्सव अगस्त 2021 में लाहौल घाटी में आयोजित किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण

224. हिमाचल प्रदेश हमारे सैनिकों की बहादुरी और देश भक्ति के लिए जाना जाता है। हमें अपने भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों पर गर्व है।

लहू देकर तिरंगे की, बुलंदी को संवारा है।
फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है।।

225. धर्मशाला में वॉर मैमोरियल के समीप एक वॉर म्यूज़ियम का निर्माण हुआ था किन्तु कुछ वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। आगामी वर्ष में इस म्यूज़ियम

को सुसज्जित करके आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

226. नूरपुर में शहीदों की याद में वॉर मैमोरियल का निर्माण कार्य 2021–22 में आरम्भ कर दिया जाएगा।

227. सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु बरछवाड़, मण्डी में Pre Coaching Sainik Academy स्थापित करने के लिए निर्माण कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। 2021–22 में 5 (पाँच) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

228. निर्भया फण्ड के तहत 2021–22 में 136 (एक सौ छत्तीस) पुलिस थानों में सहायता डेस्क स्थापित किये जाएंगे ताकि शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाना जाने वाली महिला के लिए यह डेस्क सम्पर्क का पहला बिन्दु हो। यहाँ यह कहना उचित होगा किः– गृह/कानून व्यवस्था

दिल और दिमाग में हमेशा यह बात रखिये,
दूसरों की मदद के लिए जज़्बात रखिये।

229. अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अभिभाषण में महिलाओं के सन्दर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि पुलिस विभाग में आरक्षी एवम् उप–निरीक्षक के सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिये आरक्षण चरणबद्ध तरीके से 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक ले जाया जाएगा।

230. कानून व्यवस्था में गतिशीलता तथा emergency response बढ़ाने के लिए 2021–22 में पुलिस विभाग में सभी नकारा वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध करवाये जाएंगे जिस पर 13 (तेरह) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

231. अन्वेषण की विश्वसनियता को बढ़ाने के लिए साईबर अन्वेषण एवम् फोरेंसिक सेवाओं का निरन्तर उन्नयन आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाएगा।

232. अपराधों की रोकथाम और बेहतर निगरानी के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में 757 (सात सौ सतावन) CCTV कैमरे लगाये जाएंगे और पहले से लगाये गए 651 (छः सौ इक्यावन) कैमरों का उन्नयन किया जाएगा। सभी

ज़िला मुख्यालयों पर स्थित नियन्त्रण कक्षों को आधुनिक बनाया जाएगा एवम् उनको आपस में तथा राज्य मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। पुलिस विभाग Intelligent Traffic Management System पर भी उचित कार्य करेगा। इन कार्यों के लिए 9 (नौ) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

233. हमारी सरकार के नशे के विरुद्ध दृढ़ निश्चय को और अधिक बल देने के लिए तथा प्रदेश में पूर्ण नशा निवारण हेतु 2021–22 में एक समग्र नशा निवारण नीति लाई जाएगी जिसके कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर "नशा निवारण फण्ड" की स्थापना की जाएगी।

234. पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाओं, पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह में उन्नत पुलिस प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करवाने और अन्य पूंजीगत कार्यों के लिए मैं 50 (पचास) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

235. अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 3 (तीन) नये Sub Fire Station तथा 4 (चार) नई Fire Posts स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विभाग में 17 (सतरह) अग्नि शमन वाहन भी खरीदे जाएंगे।

नये कार्यालय/ संस्थान

236. अध्यक्ष महोदय, विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार आवश्यकतानुसार विभिन्न संस्थान एवं कार्यालय आगामी वर्ष में खोलेगी। इस दिशा में नये महाविद्यालय, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी कॉलेज, विकास खण्ड, तहसील, उप–तहसील, पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, अग्निशमन केन्द्र इत्यादि खोले जाएंगे। इसके लिए जहाँ सम्भव होगा मौजूदा संसाधनों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा।

भर्तियां

237. जनता तक शासन को पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार चरणबद्ध तरीके से functional posts को भरे। अपने बजट अभिभाषण में मैंने विभिन्न स्थानों पर विभागों के सुदृढ़ीकरण करने का उल्लेख किया है।

238. हमारी सरकार अगले वर्ष स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 (चार हजार) पद; शिक्षा विभाग में

विभिन्न शिक्षकों के 4,000 (चार हजार) पद; शिक्षा विभाग में 8,000 (आठ हजार) Multi Task Part Time workers; लोक निर्माण विभाग में 5,000 (पाँच हजार) Multi Task Part Time Workers; तथा जल शक्ति विभाग में 4,000 (चार हजार) पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time workers के पद भरेगी। इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में खाली functional पदों को भरेगी जिनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, HRTC में ड्राईवर एवं कण्डक्टर, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, JOA (IT), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि शामिल हैं। इस प्रकार 2021–22 में हमारी सरकार का 30,000 (तीस हजार) से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य है।

वैकल्पिक यातायात सुविधा

239. प्रदेश में सड़कों के अतिरिक्त, अन्य यातायात साधनों में विस्तार समय की आवश्यकता है। हवाई यातायात तथा रेल लाईन विस्तार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ और प्रयासों से शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

240. चण्डीगढ़–बद्दी रेल सम्पर्क औद्योगिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेल लाईन के भूमि अधिग्रहण का कार्य 2021–22 के दौरान पूरा किया जाएगा। 2021–22 में अन्तिम 20 किलोमीटर पर भानुपल्ली–बिलासपुर रेल लाईन का भूमि अधिग्रहण भी पूरा किया जाएगा। प्रथम 20 (बीस) किलोमीटर में 7 (सात) सुरंगों और 18 (अठारह) पुलों पर काम शुरु हो गया है, जिसे और गति प्रदान की जाएगी। 2021–22 में रेल लाईन निर्माण हेतु 200 (दो सौ) करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

241. मेरी सरकार प्रदेश में जल मार्ग परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। सतलुज नदी में कसोल (बिलासपुर) व तत्तापानी के मध्य कोल डैम में जल परिवहन सेवाएं हाल ही में शुरु की गई हैं। ब्यास, चिनाव, रावी और सतलुज नदियों एवं जलाशयों में यात्रियों एवं मालभार परिवहन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।

242. पर्यावरण तथा सम्बन्धित clearances (अनुमति) में आने वाली कठिनाई के दृष्टिगत् हमारी सरकार ने रज्जू मार्गों के निर्माण पर भी बल दिया है। बगलामुखी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए प्रारम्भ की गईं प्रक्रियाओं को गति प्रदान की जाएगी। प्रदेश का रज्जु मार्ग विकास निगम दुर्गम क्षेत्रों में यात्रियों और सामग्री के लिए कम्पोज़िट रोप–वे निर्माण पर तेज़ी से काम करेगा। प्रदेश में रज्जू मार्गों के निर्माण के लिए 2021–22 में 25 (पच्चीस) करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

243. प्रदेश को देश के नागरिक उड्डयन मानचित्र पर उचित पहचान दिलाने के लिए मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य हेतु मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण और काँगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। इन परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए 2021–22 के लिए 1,016 (एक हज़ार सोलह) करोड़ रुपये के परिव्ययों का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना

244. अध्यक्ष महोदय, लोगों को आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के साथ–साथ मेरी सरकार ने उनके जीवन स्तर के उन्नयन के लिए बहुत से सकारात्मक पग उठाये हैं। मैंने पिछले बजट अभिभाषण में 'स्वर्ण जयन्ती आश्रय' योजना की घोषणा की थी। इस योजना का व्यापक स्वागत हुआ था। कोविड के कारण योजना के कार्यान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ है। अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मैं इस योजना के अन्तर्गत 12 (बारह) हज़ार लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। पिछले वर्ष यह संख्या 10 (दस) हज़ार थी। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा किः–

सब चाहते हैं कि उनका अपना एक घर हो,
मैं चाहता हूँ सबका ये सपना सच हो।

245. पिछले वर्ष के संकल्प की पुष्टि करते हुए मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। 2021–22 के दौरान स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना हेतु 180 (एक सौ अस्सी) करोड़

रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 (बीस) करोड़ रुपये अधिक हैं।

कर्मचारी कल्याण

246. मैं ज़िला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवम् कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही माँग के दृष्टिगत् जिलों में सरकारी आवासों के रख–रखाव एवं मुरम्मत के लिए 2021–22 में 36 (छत्तीस) करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ। सरकारी कार्यालयों की उचित देखभाल के लिए भी मैं 115 (एक सौ पन्द्रह) करोड़ रुपये तथा सरकारी आवासीय भवनों के रख–रखाव के लिये 42 (बयालीस) करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

247. अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 (बीस) वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद मिलने वाली वेतन वृद्धि में विसंगति को दूर किया जाएगा जिससे सभी कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि 20 (बीस) वर्षों की अवधि पूरा होने के बाद एक समान मिल सकेगी।

248. अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी Ministerial Cadre में Limited Direct Recruitment तथा बारी आने पर पदोन्नत हो सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि वे Junior Office Assistant (IT) के पद पर भी पदोन्नत हो सकेंगे।

249. सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए बजट बढ़ाकर 100 (सौ) करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

250. दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी 275 (दो सौ पचहतर) रुपये से बढ़ाकर 300 (तीन सौ) रुपये प्रतिदिन किये जाने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ। अन्य दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी भी इसी अनुपात में बढ़ाई जाएगी। अंशकालिक कर्मियों की प्रति घंटा दरों में भी बढ़ौतरी की जाएगी।

251. कई बार इस सदन में भी यह चर्चा हुई कि आऊटसोर्स पर लगे कर्मियों का सेवा प्रदाता शोषण करते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि Model Tender Document बनाकर

समस्त विभागों को भेजा जाएगा जिससे कि पूरे प्रदेश में इन कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके।

252. मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 3 (तीन) वर्षों में दैनिक भोगी एवं आऊटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम स्तर पर प्रतिमाह मिलने वाली राशि में 2,700 (दो हजार सात सौ) रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है जो कि 42 (बयालीस) प्रतिशत से अधिक है।

253. हमारी सरकार ने 2019 में करुणामूलक आधार की नियुक्तियों बारे संशोधित नीति जारी की थी जिसके तहत आय सीमा में बढ़ौतरी और पात्रता के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई थी। हम इस नीति की समीक्षा करेंगे ताकि इसके तहत जरूरतमंद पारिवारिक सदस्यों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

254. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को 2003 में लागू किया गया था। हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किये हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अँशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। इसमें प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होता है। दूसरा, वर्ष 2020 में सितम्बर, 2017 से पूर्व सेवानिवृत/मृत NPS कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत ग्रेच्युटी भी प्रदान की गई है जिसमें 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्तत व्यय होगा। हमारी सरकार NPS कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

255. हमारी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों/पेंशनरों को संशोधित वेतनमान/पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बजट अनुमान

256. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण राज्यत्व के 51वें वर्ष में मैं माननीय सदन के साथ प्रदेश की विकास यात्रा को दर्शाती यह रोचक जानकारी सांझा करना चाहता हूँ। वर्ष 1971–72 के लिए प्रदेश का कुल बजट 80.18 करोड़ (अस्सी करोड़ अट्ठारह लाख) रुपये का था। आज मैं वर्ष 2021–22 के लिए 50,192 (पचास हजार एक सौ बानबे) करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह माननीय

सदन तथा प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के राज्यत्व के पचास वर्ष पूरे होने पर हमारी सरकार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत कर रही है।

257. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2020–21 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 35,588 (पैंतीस हज़ार पाँच सौ अट्ठासी) करोड़ रुपये हैं। 2020–21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 36,011 (छत्तीस हजार ग्यारह) करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा 423 (चार सौ तेईस) करोड़ रुपये अनुमानित है।

258. अध्यक्ष महोदय, 2021–22 का कुल बजट 50,192 (पचास हज़ार एक सौ बानवे) करोड़ रुपये का है। वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्तियां 37,028 (सैंतीस हज़ार अट्ठाईस) करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 38,491 (अठ्तीस हजार चार सौ इकानवे) करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 1,463 (एक हजार चार सौ तरेसठ) करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 7,789 (सात हज़ार सात सौ नवासी) करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.52 प्रतिशत है।

259. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों में नए कर का प्रस्ताव नहीं है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी कर अनुपालन, भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

260. 2021–22 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 25.31 रुपये, पैंशन पर 14.11 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 6.64 रुपये, जबकि शेष 43.94 रुपये विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है।

261. 2020–21 में कोरोना के कारण प्रदेश के संसाधनों पर प्रभाव पड़ा है। 2021–22 में भी राजस्व संसाधनों पर इस प्रभाव के रहने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस कारण 2021–22 में FRBM Act के कुछ लक्ष्य प्राप्त होने में संशय है। प्राकृतिक आपदा की अवस्था में FRBM Act के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है। तदानुसार FRBM Act के अनुरूप विवरण इस बजट के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

262. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुख्य बिन्दु संलगित अनुबन्ध में निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, जनकल्याण को समर्पित तथा लोक हित के मूल्यों से पोषित, लोकतान्त्रिक सरकार के लिए बजट केवल आगामी वर्ष की प्रस्तावित आय और व्यय का अनुमान भर नहीं है बल्कि हमारे लिए यह प्रदेश की जनता की आकाँक्षाओं को पूर्ण करने का जीवंत दस्तावेज़ है।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, सबके लिए आवास, कृषक उत्थान, शिक्षा में गुणवत्ता, कनेक्टिविटी तथा रोज़गार सृजन इस बजट के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। हमारी प्राथमिकता सदैव की भाँन्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा जरूरतमंद समूहों का कल्याण है। यह बजट उद्यमिता एवम् कौशल विकास, पर्यटन तथा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। मेरी सरकार प्रत्येक प्रदेशवासी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरन्तर और अथक् परिश्रम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है।

हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो।
चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो।।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बजट माननीय सदन को संस्तुत करना चाहूँगा।

जय हिन्द – जय हिमाचल

बजट साराँश

- ✶ 50,192 करोड़ रुपये का बजट जो कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है।
- ✶ अर्थव्यवस्था में V-Shaped Recovery
- ✶ पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में कई कार्यक्रमों का आयोजन

यह बजट निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित हैः–

- ☞ **महिला कल्याण और सशक्तिकरण**
- ☞ **सामाजिक सुरक्षा विस्तार**
- ☞ **स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार**
- ☞ **किसानों की आय में वृद्धि**
- ☞ **स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना**
- ☞ **रोज़गार सृजन**
- ☞ **औद्योगिक विकास व आधारभूत ढाँचे पर बल**
- ☞ **शिक्षा में गुणवत्ता**

1. महिला कल्याण और सशक्तिकरण

- ''**स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना**'' के अन्तर्गत 65–69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिस पर 55 करोड़ रुपये कीअतिरिक्त राशि व्यय की जायेगी।

- ''**शगुन"** नाम से नई योजना का शुभारम्भ। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हज़ार रुपये का अनुदान। योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।

- BPL परिवारों को दो लड़कियों तक अब 21 हज़ार रुपये की Post Birth ग्रांट फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाएगी।

- Self Help Groups के लिये पहल। अनेक योजनायें घोषित।

- ''**हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना**'' के अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफ़िल अगले वर्ष भी दिया जाएगा।

- 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित होगा।

- पुलिस में आरक्षी एवम् उप–निरीक्षक के लिये चरणबद्ध समय में 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित।

- बैंकिंग सेवायें प्रदान करने हेतु 250 महिलाओं को "Bank Correspondent Sakhi" के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

2. सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

- 40 हज़ार अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।

- हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 लाख 60 हजार लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाये गये हैं जिस पर 1,050 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

3. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- IGMC में PET स्कैन की सुविधा, टांडा मेडिकल कॉलेज में CT Scan तथा MRI मशीनें तथा हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में CT Scan मशीनें लगाई जाएंगी। इनके लिये 70 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

- चमयाना के सुपर स्पैशिलिटि अस्पताल, IGMC के OPD Block तथा ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा।

- 70 वर्ष से अधिक आयु के हिमकेयर लाभार्थियों तथा बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिमकेयर में अंशदान से छूट।

- कक्षा छः से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आँखों की जाँच एवं निःशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए **"मिशन दृष्टि"** आरम्भ करना।

- कुपोषण की समस्या के निदान के लिये नीति आयोग, भारत सरकार की भागीदारी से अध्ययन करवाया जाएगा।

- आयुष्मान भारत, हिम केयर, मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, निःशुल्क दवाईयाँ, सहारा योजना, सम्मान योजना, निक्षय पोषण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश सरकार 2021–22 में 250 (दो सौ पचास) करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेगी।

4. किसानों की आय में वृद्धि

- उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए नई **"स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान"** योजना।

- **''कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना''** (KUSHY) में बजट की बढ़ौतरी। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।

- कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुसन्धान कोष स्थापित किया जाएगा।

- विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत पाँच लाख पौधों का आयात, 8 हज़ार हैक्टेयर Command Area के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni में Gene Repository की स्थापना तथा पराला शिमला स्थित संयन्त्र में Apple Juice Concentrate Plant की स्थापना।

- **''प्राकृतिक खेती–खुशहाल किसान योजना''** के अन्तर्गत 50 हज़ार नये किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा।

- दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया।
- कृषि एवम् सम्बन्धित क्षेत्र में योजनाओं को पुनर्भाषित करने तथा किसानों/बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए Expert Group गठित किया जाएगा।

5. स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/अनुसूचित जाति कल्याण

- ''**स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना**'' के अन्तर्गत 12 हज़ार लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने का लक्ष्य निर्धारित।
- 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा।

6. रोज़गार सृजन

- ''**मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना**'' का विस्तार और बजट में बढ़ौतरी–100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोज़गार।
- Building and Construction Workers Welfare Board के माध्यम से कामगारों को और सहायता दी जाएगी।
- 2021–22 में हमारी सरकार का 30,000 (तीस हजार) से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 (चार हजार) पद; शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000 (चार हजार) पद; शिक्षा विभाग में 8,000 (आठ हजार) Multi Task Part Time workers; लोक निर्माण विभाग में 5,000 (पाँच हजार) Multi Task Part Time Workers; तथा जल शक्ति विभाग में 4,000 (चार हजार) पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time workers के पद भरेंगे। इनके अतिरिक्त सरकार विभिन्न विभागों में खाली functional पदों को भरेगी जिनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, HRTC में ड्राईवर एवं कण्डक्टर, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के

लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, JOA (IT), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि शामिल हैं।

- कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना–2018 के अन्तर्गत अब ऑनलाईन पंजीकरण।

7. औद्योगिक विकास व आधारभूत ढाँचे पर बल

- अटल सुरंग पर (दोनों ओर) पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग, Wayside Amenities की स्थापना।
- लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रख–रखाव के लिये 5,000 पार्ट टाईम Multi Task Worker रखे जाएंगे।
- 10,000 करोड़ रुपये के MOU की नई ग्राऊंड ब्रेकिंग की तैयारी।
- ऊना जिला में ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
- नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क का प्रस्ताव।
- नालागढ़ में इलैक्ट्रोनिक्स और पॉवर इक्युपमेंट हब का प्रस्ताव।
- खिलौना क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे।
- प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,125 किलो मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन।
- 140 किलोमीटर सड़कों पर W-Metal बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।
- 2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य। Black Top सड़कें जो अभी 30,244 किलोमीटर लम्बी हैं, 2022 तक 34,000 किलोमीटर कर दी जाएगी।
- 2021–22 के दौरान प्रदेश में दो हज़ार किलोमीटर मैटलिंग एण्ड टॉरिंग, 1 हज़ार किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 80 पुलों

का निर्माण, 90 गांवों को सड़क सुविधा, 8 सौ किलोमीटर सड़कों का उन्नयन तथा 2 हज़ार 200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा।

- शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक योजनायें शुरु और जनता को समर्पित की जायेंगी।
- नव गठित सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को एक–एक करोड़ रुपये तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20–20 लाख रुपये विशेष अनुदान।
- प्रदेश में अनेक मल निकासी योजनाओं पर तीव्रता से काम किया जाएगा।
- स्वर्ण जयन्ती ऊर्जा नीति लाई जाएगी और Power Vision Document 2030 तैयार किया जाएगा।
- बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिये अनेक कदम।
- पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिये Multi Media Publicity Campaign शुरु किया जाएगा।
- पर्यटन उद्योग की अनेक योजनायें जनता को समर्पित की जाएंगी। 218 करोड़ रुपये की 19 योजनायें मनाली, जंजैहली, मण्डी, धर्मशाला, क्यारीघाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, शिमला, भलेई माता चम्बा, बीड़ बिलिंग, हाटकोटी, कांगनीधार, रामपुर और बद्दी में, 2021–22 में, जनता को समर्पित की जायेंगी।
- जल जीवन मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते हुये तीन और जिलों सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में शत प्रतिशत पीने के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे।
- मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण और काँगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। 2021–22 में 1,016 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को ODF मानदण्डों पर सुदृढ़ किया जाएगा। कूड़े की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा।

- पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 नई बसें।

- रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।

8. शिक्षा में गुणवत्ता

- ''**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**'' का स्वागत और उसके लागू करने का संकल्प।

- **"टॉप 100 छात्रवृति योजना"** का शुभारम्भ।

- 100 स्कूलों में Math Lab की स्थापना।

- सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग एवं कैरियर काँउसलिंग सुविधा।

- शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु ''**हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल**'' की स्थापना।

- स्कूल टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों की डाइट मनी दोगुनी की गई।

- ''**स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना**'', ''**स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना**'' तथा ''**उत्कृष्ट योजना**'' के अन्तर्गत क्रमशः 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

- तकनीकी शिक्षा विभाग के 400 करोड़ रुपये के 8 संस्थान जनता को समर्पित किये जायेंगे जो ज्यूरी, सुन्दरनगर, कुमारसेन, अर्की, गंगथ, करसोग, रैहन, बन्दला में स्थित हैं।

- IT और SMC शिक्षकों के मानदेय मे बढ़ौतरी।

9. अन्य

- आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के पार्टटाईम वाटर कैरियर और मिड डे मील

वर्कर, राजस्व विभाग के अंशकालिक वर्कर और नम्बरदार, जल गार्ड, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि।

- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये नये कॉलेज़, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी कॉलेज, विकास खण्ड, तहसील, उप–तहसील, पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, अग्निशमन केन्द्र इत्यादि खोले जाएंगे। जहाँ सम्भव होगा मौजूदा संसाधनों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा।
- ''**विकास में जन सहयोग**'' कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्ययों को दोगुना किया।
- विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया।
- "**Swaran Jayanti District Innovation Fund**" स्थापित होगा।
- नवगठित पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण होगा।
- 'समग्र नशा निवारण नीति' लाने का प्रस्ताव और ''**नशा निवारण फण्ड**'' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई। अंशकालीन कर्मी और आऊटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी।
- प्रदेश के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाये जाएंगे
- आऊटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के लिये पग उठाये जाएंगे।

****